शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 250 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

परिसीमन के जरिए राजनीतिक हित साध रही सरकार : प्रियंका पेज 2
मेघालय : अंग्रेजी के साथ-साथ खासी और गारो आधिकारिक भाषाएं बन गईं पेज 3
भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण... पेज 5
बायर्न म्युनिख ने रियल मैड्रिड को हराकर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बनाई जगह पेज 7

बंगाल में ममता पर जमकर बोले असम सीएम हिमंत विश्व शर्मा, कहा–

मैं बांग्लादेशियों को लात मारकर भेज देता हूं, दीदी दुल्हन की तरह बुला लेती हैं

कोलकाता। असम विधानसभा के लिए वोटिंग के बाद सीएम हिमंत विश्व शर्मा पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। बंगाल में भी वह अपने अंदाज में ही भाषण दे रहे हैं। कूचबिहार में असम के सीएम ने पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। चुनावी सभा में हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा का सरकार लाना है। क्यों लाना है आप लोग देखिए। असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद करा दिया है। असम में पूरा ताला लगा चुका हूं। एक बांग्लादेशी आता है तो मैं लात मारकर रात में ही वापस भेज देता हूं। लेकिन मैं क्या करूं, असम से मैं भगा देता हूं, मगर ममता जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को दुल्हन की तरह बुला लेती हैं। इसका कोई फायदा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल और असम में धीरे-धीरे हिंदू कम हो जाएगा। हिमंत विश्व शर्मा ने टीएमसी के नॉनवेज वाले नैरेटिव को भी तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आप असम में आइए, हमारे पास बेहतरीन नॉनवेज फूड है। क्या किसी ने आपसे कहा है कि नॉन-वेज खाना बंद कर दिया जाएगा? तो फिर ममता दीदी क्यों डर रही हैं? वह इसलिए डर रही हैं क्योंकि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो हम

गोमांस और गो-हत्या पर रोक लगा देंगे। हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि वह असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो यह कानून यहां भी लागू किया जाएगा। ममता दीदी इसलिए भी डर रही हैं क्योंकि भाजपा बहु-विवाह की इस फैक्ट्री पर भी रोक लगा देगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में असम भाजपा के 50 से अधिक नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। असम और बंगाल की सीमा 127 किलोमीटर तक कॉमन है। अलीपुरद्वार और जलपाई गुड़ी जिले की सीमा असम से जुड़ती है। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को अखिल भारतीय -शेष पृष्ठ दो पर

भाजपा पश्चिम बंगाल में *डबल सेंचुरी* पार करेगी : डॉ. शर्मा

सिलीगुड़ी (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में भाजपा *डबल सेंचुरी* यानी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने यह बातें कही। वह फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रत्याशी दुर्गा मुर्मू के समर्थन में खोरीबाड़ी के बतासी पीएसए मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राज्य की सत्तारूढ़ सरकार तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असम चुनाव में व्यस्त रहने के कारण वे पहले नहीं आ सके, लेकिन चुनाव खत्म होते ही पार्टी के निर्देश पर प्रचार के लिए यहां पहुंचे है। उन्होंने राज्य सरकार -शेष पृष्ठ दो पर

रिनिकी शर्मा मामले में खेड़ा को एससी से राहत नहीं, गिरफ्तारी की लटकी तलवार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उसने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुईयां शर्मा द्वारा दायर एक मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए दी गई अग्रिम छूट पर रोक लगा दी है। असम में दर्ज एफआईआर, खेड़ा के इस दावे पर आधारित है कि उनके पास कई देशों के पासपोर्ट हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 10 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने पवन खेड़ा को कुछ शर्तों के साथ एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दी, जिससे उन्हें आगे की राहत -शेष पृष्ठ दो पर

हिमंत शर्मा का राहुल गांधी को चैलेंज- हिम्मत है तो अपना पासपोर्ट दिखाएं

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को पासपोर्ट विवाद में रिनिकी भुईयां शर्मा द्वारा दर्ज एफआईआर के संबंध में दी गई एक सप्ताह की ट्रांजिट जमानत पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया। जब उनसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिमंत की पत्नी रिनिकी भुईयां शर्मा के खिलाफ कई पासपोर्टों के आरोपों की जांच

की मांग के बारे में पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता से सार्वजनिक रूप से अपना पासपोर्ट दिखाने को कहा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि मेरे अनुसार, तेलंगाना कोर्ट ट्रांजिट जमानत नहीं दे सकता क्योंकि वह तेलंगाना के निवासी नहीं हैं। कानून अपना काम करेगा... अगर मैं उन पर ऐसे आरोप लगाऊं तो क्या -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

जो नास्तिक हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान में विश्वाश करना चाहिए इसी में उनका हित है।

– ईश्वर चंद्र विद्यासागर

त्रिपुरा टीटीएडीसी चुनाव

पोलिंग स्टेशन पर हिंसा : भाजपा विधायक समेत 35 पर एफआईआर

सोनमुरा (हि.स.)। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएडीसी) चुनाव के लिए वोटिंग के दिन सिपाहीजला जिले के बॉक्सनगर में एक पोलिंग स्टेशन के आसपास हुई हिंसा मामले में भाजपा

विधायक तफज्जल हुसैन और कुल 35 लोगों के खिलाफ कलमचौरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह शिकायत टिपरा मोथा दल के सदस्य अभिराम देबबर्मा ने दर्ज कराई है। उनका -शेष पृष्ठ दो पर

अब, बाढ़ की भविष्यवाणी करने वाले एआई उपकरण पूर्वोत्तर के छह राज्यों में किसानों की करेंगे मदद

सिलचर। बाढ़ की भविष्यवाणी करने से लेकर किसानों को फसल चयन में मार्गदर्शन देने तक, एक नई एआई-संचालित प्रणाली बराक नदी बेसिन और उससे आगे के क्षेत्रों में कृषि को नया आकार दे रही है। सिलचर स्थित असम विश्वविद्यालय द्वारा विकसित यह परियोजना पूर्वोत्तर के किसानों के हाथों में भविष्यसूचक बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय की जानकारी सीधे पहुंचा रही है। विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के नेतृत्व में, 2024 में परिकल्पित इस पहल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसकी निगरानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई द्वारा की जा रही है। असम, त्रिपुरा,

मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड सहित छह राज्यों को कवर करते हुए, यह एक ऐसे क्षेत्र को संबोधित करता है जहां कृषि अनियमित मौसम और समय पर जानकारी तक सीमित पहुंच के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है। कृषि में प्रौद्योगिकी अक्सर सलाह तक ही सीमित रह जाती है। हम इससे आगे बढ़कर पूर्वानुमान, पहुंच और कार्रवाई को एक एकीकृत प्रणाली में जोड़ना चाहते थे, सहायक प्रोफेसर और प्रधान शोधकर्ता डॉ. सोमनाथ मुखोपाध्याय ने -शेष पृष्ठ दो पर

हरिवंश का रास का उपसभापति बनना तय आज आएगा प्रस्ताव

नई दिल्ली। हरिवंश का राज्यसभा का उपसभापति सर्वसम्मति से बनना तय है। शुक्रवार को इस बाबत राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा। उपसभापति के चुनाव के लिए प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख और समय गुरुवार, 16 अप्रैल को दोपहर 12:00 बजे तक था। आज तय समय के अंदर उपसभापति पद के लिए पांच प्रस्ताव मिले। पांचों में हरिवंश को राज्य सभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव किया गया था। जो पांच प्रस्ताव दिए गए, उनमें पहले प्रस्ताव में बीजेपी सांसद जगत प्रकाश नड्डा प्रस्तावक हैं और एस फांगनोन कोन्याक अनुमोदक हैं। दूसरे प्रस्ताव में भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष नितिन नबीन प्रस्तावक हैं और बृज लाल अनुमोदक हैं। तीसरे प्रस्ताव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्तावक हैं और अनुमोदक सुरेंद्र सिंह नाग हैं। चौथे -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

आश्रम स्कूल में जहरीला खाना खाने से सौ बच्चे बीमार, एक छात्रा की मौत

रायरंगपुर। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रासगोबिंदपुर क्षेत्र स्थित काकाबंध आश्रम स्कूल में विषाक्त भोजन खाने से सैकड़ों छात्र-छात्राएं बीमार हो गए, जबकि उपचार के दौरान एक पांचवीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। -शेष पृष्ठ दो पर

महिला आरक्षण विधेयक पर पीएम मोदी की विपक्ष को सीधी चेतावनी-

विरोध की लंबी कीमत चुकानी पड़ेगी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राजनीतिक स्वरूप के साथ देश की दशा और दिशा तय करने वाला है। मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है; अतीत में जिन्होंने विरोध किया, महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। मोदी ने कहा

कि राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं, और उस समय की समाज की मन स्थिति एवं नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर कर एक राष्ट्र की अमानत बना देती हैं, एक मजबूत धरोहर तैयार करती हैं। भारत के संसदीय इतिहास में ये वैसा ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले, जब ये विचार सामने आया तभी इसे लागू कर देते। आज हम इसे काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते। आवश्यकतानुसार उसमें समय समय पर सुधार होते और यही तो -शेष पृष्ठ दो पर

नोएडा बवाल : सीमा पार से भड़काए गए थे श्रमिक अब तक 13 एफआईआर

नोएडा। शहर में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के पीछे पाकिस्तान से संचालित एक्स हैंडलर का हाथ सामने आया है। पुलिस ने दो ऐसे एक्स हैंडलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने यह जानकारी दी। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर भड़की इस हिंसा की चिंगारी तेलंगाना और कर्नाटक से वॉट्सऐप के -शेष पृष्ठ दो पर

राज्यों का नहीं घटेगा प्रतिनिधित्व, परिसीमन भी पहले जैसी प्रक्रिया से होगा : शाह

नई दिल्ली (हि.स.)। गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि से राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनित्व प्रतिशत पहले के भांति बना रहेगा। वहीं,

सरकार पिछली बार देश में हुई परिसीमन की प्रक्रिया को ही दोहराएगी। इससे जुड़ा विधेयक कांग्रेस के परिसीमन अधिनियम जैसा ही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार की ओर से लाए गए तीन विधायकों से जुड़ी भ्रांतियां को दूर करने के लिए लोकसभा में आज चर्चा का संक्षिप्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह विषय पर विस्तार से अपनी -शेष पृष्ठ दो पर

कोलकाता के सौ से ज्यादा बूथों पर बिजली गुल, ईसी ने दिए तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश

कोलकाता। विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कोलकाता जैसे महानगर के 100 से अधिक मतदान केंद्रों (बूथों) में बिजली की सुविधा नहीं है। यह जानकारी

मिलने के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी भी हैरान हैं। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर बूथ पर मतदान के दौरान आधुनिक वेब कास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लेकिन बिना बिजली के यह संभव नहीं है। इसीलिए जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को तुरंत सभी बूथों में बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। जहां बिजली की व्यवस्था संभव नहीं है, वहां जेनरेटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के अधिकांश मतदान केंद्र स्कूलों में बनाए जाते हैं। दक्षिण कोलकाता के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशों को -शेष पृष्ठ दो पर

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जंग की आहट!

कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिका ने सैनिक भी बढ़ाए, ईरान ने दी खुली चेतावनी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां एक ओर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य और आर्थिक टकराव तेज हो गया है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। हाल के घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि स्थिति अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है और किसी भी समय व्यापक संघर्ष का रूप ले सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई

ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ईरान हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रत्येक बंधक के बदले भारी आर्थिक कीमत वसूली जाएगी। मोहसिन रजाई ने यह भी दावा किया कि यदि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी नाकाबंदी जारी रखी, तो ईरान अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना -शेष पृष्ठ दो पर

तुर्की के स्कूल में भीषण गोलीबारी, 13 साल के लड़के ने की नौ लोगों की हत्या

अंकारा। तुर्की में एक छात्र ने एक स्कूल में गोलीबारी की, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। दो दिनों में यह देश में इस तरह की दूसरी घटना है। इस हमले के

बाद 14 वर्षीय हमलावर भी मारा गया। कहारमनमारास प्रांत के गवर्नर मुकर्रेम उनलुएर ने बताया कि वह अपने पिता, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं, की बंदूकें लेकर स्कूल पहुंचा था। उसके पास पांच बंदूकें और सात मैगजीन थीं। इस हमले का मकसद तुरंत पता नहीं चल पाया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हमलावर पुलिस की गोलीबारी में मारा गया या उसने खुद को मार डाला। गृह मंत्री मुस्तफा सिफ्टसी ने बताया कि घायल 13 लोगों में से छह की हालत गंभीर है। दरअसल -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

सीएम डॉ. शर्मा बांग्लादेश पर अपनी *मनमानी* टिप्पणी को लेकर कर रहे हैं विपक्ष के हमले का सामना

गुवाहाटी। असम में विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की विभिन्न मुद्दों पर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए उनकी *मानसिक स्थिरता* पर सवाल उठाया है और उन्हें *अहंकार से मदहोश तानाशाह* और *मनोवैज्ञानिक रोगी* बताया है। एक टीवी समाचार प्रसारक को दिए साक्षात्कार में, शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों, घुसपैठ और प्रतिशोध अभियानों, भारत-बांग्लादेश संबंधों और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई मुद्दों पर बात की। संपर्क करने पर भाजपा ने शर्मा के साक्षात्कार और उसकी विषयवस्तु पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबव्रत सैकिया ने कहा कि मैं शर्मा की अलोकतांत्रिक, गैर-जिम्मेदार और अप्रासंगिक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता हूं, जिन्होंने मुख्यमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। शर्मा ने राष्ट्रीय मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में मनमानी और दमनकारी टिप्पणियां की हैं, जो शर्मनाक है। उन्होंने आगे कहा कि शर्मा के साक्षात्कार से यह साबित हो गया है कि सत्ता के अहंकार में उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थानों के प्रति न्यूनतम सम्मान भी खो दिया है। हम उनकी टिप्पणियों का कड़ा विरोध करते हैं। असम पुलिस के प्रति घोर पाखंड और अपमान है। जुबीन गर्ग मामले के दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि असम पुलिस सिंगापुर पुलिस से बेहतर है। आज वे अपनी राजनीतिक विफलता को छिपाने के लिए उसी पुलिस बल को *बुरा* कह रहे हैं, उन्होंने कहा। अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के मुद्दे पर, शर्मा ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है और असम सीमावर्ती क्षेत्रों में *अंधेरे का फायदा उठाकर* उन्हें वापस भेजने के अभियान चलाता है, जहां पड़ोसी पक्ष में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि *भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कभी बेहतर न हों,* उनका दावा है कि जब दोनों देशों के बीच संबंध घनिष्ठ होते हैं तो असम को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साइकिया ने कहा कि यह *अवैध कृत्यों* की स्वीकारोक्ति के बराबर है और उन्होंने इसे गैर-जिम्मेदार विदेश नीति संबंधी टिप्पणी बताते हुए इसकी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि एक मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध कभी बेहतर न हों! अंधेरे का फायदा उठाकर जवाबी कार्रवाई की उनकी स्वीकारोक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर मजाक है। शर्मा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को *पागल* करार दिया और ग्रोक द्वारा किए गए *52 पात्रों* के विश्लेषण के अनुसार उन्हें *इलाज* की आवश्यकता बताई। इसे राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताते हुए सैकिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पागल कहना उनकी राजनीतिक दिवालियापन का प्रमाण है। एक राष्ट्रीय नेता का कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐप के संदर्भ में अपमान करना स्वयं मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिरता पर सवाल उठाता है। शर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद, वह *लोकतंत्र की पवित्रता* के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगे। असम जातीय परिषद (एजेपी) के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई ने भी मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए उनके बयानों को *असंतुलित* और *तर्कहीन* बताया। उन्होंने कहा कि यह मनोवैज्ञानिक मामला है।

असम भाजपा मुख्यालय में जापान के प्रतिनिधियों के साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने की चर्चा

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में जापान कांसुलेट के प्रथम सचिव मयुमी स्तबाकिमोतो और राजनीति विभाग के वरिष्ठ सहायक कृष्ण मनीष चौधरी की उपस्थिति में भारत और जापान के संबंधों के विषय में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। एक बयान में असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रांजल कलिता ने बताया कि जापान की दृष्टि में असम में संभावनाएं, निवेश-व्यवसाय, महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति का विकास, भाजपा पार्टी के आदर्श, असम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आदि कई महत्वपूर्ण विषयों पर उपस्थित प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श किया।

परिसीमन के जरिए राजनीतिक हित साध रही सरकार : प्रियंका

नई दिल्ली (हि.स.)। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को धर्मसंकट में डालकर मनमानी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की बात कह कर सरकार परिसीमन के माध्यम से चुनावी हित साधना चाहती है। प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा में परिसीमन और उसके माध्यम से देश में महिला आरक्षण लागू किए जाने से जुड़े संविधान संशोधन एवं दो अन्य विधेयकों पर जारी चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार देश को गुमराह कर रही है और कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के इस प्रयास का डटकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है ताकि वह जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से बच सके। उन्होंने कहा कि सरकार लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत का इजाफा कर रही है लेकिन इससे जुड़े अधिनियम में यह कैसे किया जाएगा, इसके बारे में साफ नहीं है। सरकार केवल खोखले आश्वासन दे रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि विधेयक में संसद का 50 प्रतिशत विस्तार प्रस्तावित है लेकिन इसके लिए किसी ठोस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। इतने बड़े परिवर्तन में क्या नियम होंगे, कैसे किया जाएगा, इस बारे में विधेयक में कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में देश के हर राज्य की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई और इस पर बदलाव लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के जरिए यह सब बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री के खोखले वादों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन में बदलाव किया जाएगा।

सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दो गंभीर

गोलाघाट (हिंस)। गोलाघाट जिले के ढेकियाल में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। दोनों की स्थिति बेहद चिंताजनक बतायी गयी है। यह हादसा पंडित हेमचंद्र गोस्वामी मार्ग पर हुआ। गोलाघाट पुलिस ने गुरुवार को बताया है कि पंडित हेमचंद्र गोस्वामी मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इससे दोनों बाइकों (एएस-05एल-4754 और एएस-06एक्स-3097) पर सवार तीन व्यक्ति हादसे की चपेट में आ गए। इस दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रुप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची ढेकियाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

धरमपुर गांव के नामघर से सोना-चांदी के आभूषण एवं दानपात्र की चोरी

गोलाघाट (हिंस)। गोलाघाट जिला के देरगांव के धरमपुर गांव में स्थित नामघर (पूजा स्थल) में बीती रात चोरी की घटना प्रकाश में आई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना कर चोरों की तलाश में जुटी गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि बीती रात देरगांव में एक सनसनीखेज चोरी की घटना हुई। देरगांव के राजस्व चक्र अंतर्गत मिठामरा मौजा के धरमपुर गांव में स्थित नामघर में चोरों का एक गिरोह घुसकर लूटपाट की। नामघर के गुरु आसन पर रखे सोने-चांदी के आभूषण, नकद धन और दानपात्र को चोर अपने साथ उठाकर ले गए। नामघर के नामघरिया (पुजारी) आज सुबह जब साफ-सफाई करने के लिए अंदर गए तो उन्होंने मनिकूट के दरवाजे के कुछ हिस्से को टूटा हुआ पाया। चोरों ने पैसे की तलाश में नामघर के कीर्तन की पुस्तकों को भी बर्बाद कर दिया। नामघर में नामघरिया ने बताया कि जब बीते बुधवार की देर शाम को दीपक जलाया था, तब सब कुछ ठीक था। उसके तुरंत बाद यह घटना हुई। बिहू के दिन हुई इस चोरी की घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। देरगांव पुलिस हरिमंदिर में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने गांव वालों को आश्वासन दिया है कि चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नशे में धुत व्यक्ति ने अपने घर में लगाई आग

गोलाघाट (हिंस)। गोलाघाट जिलांतर्गत बोकाखात इलाके में कथित तौर पर एक व्यक्ति द्वारा नशे में धुत होकर अपने घर में आग लगाए जाने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। असमिया नव वर्ष के बोहाग माह के पहले दिन यानी बुधवार रात को बोकाखात में एक भयानक आग लगने की घटना प्रकाश में आई। यह आग बोकाखात नगरपालिका के 9 नंबर वार्ड के पूर्व ज्योतिपुर मोहमाइकी गांव में लगी। पारिवारिक कलह के कारण नशे की हालत में धुत भाइटी राजोवा नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को पीटकर घर से भगा दिया और फिर अपने घर में आग लगा दी।

पृष्ठ एक का शेष

मैं बांग्लादेशियों को ...

तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) पर यह झूठा दावा करने का आरोप लगाया कि अगर भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतती है तो वह मांस और मछली का सेवन बंद कर देगी। उत्तर बंगाल में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शर्मा ने जोर देकर कहा कि भगवा पार्टी शासित असम में कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना मांसाहारी भोजन खा सकता है। उन्होंने कहा कि असम में एकमात्र प्रतिबंध गोमांस के सेवन पर है। आप धुबड़ी या गोलपारा जा सकते हैं और जितना चाहें मछली और मांस खा सकते हैं; कोई प्रतिबंध नहीं है, शर्मा ने कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि (मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी को चिंता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद यहां गोमांस का व्यापार बंद हो जाएगा। शर्मा ने यह भी दावा किया कि एआईटीसी बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी जारी रखना चाहता है ताकि वे अपनी जेबें भर सकें। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में मवेशियों की कथित तस्करी की जांच कर रही हैं। शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल को ऐसी सरकार की जरूरत है जो राज्य में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को उचित *व्यवहार* प्रदान करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में भाजपा को विजयी बनाना होगा। शर्मा ने कहा कि असम में भाजपा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बांग्लादेशी मुसलमान पूर्वोत्तर राज्य में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा न कर सकें। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन से बेदखल कर दिया है। यह देखते हुए कि असम सरकार के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, शर्मा ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य होने के बावजूद, यहां के सरकारी कर्मचारियों को *केवल 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता* मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि असल में उन्हें डर है कि भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य में गौ तस्करी बंद हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में विभिन्न चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भाजपा सत्ता में आई तो मछली और मांस पर प्रतिबंध लगा देगी। हिमंत विश्व शर्मा ने उसी टिप्पणी के संदर्भ में यह पलटवार किया। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव दो चरणों में, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

भाजपा पश्चिम बंगाल में ...

को *माफिया, मनी और मर्डर की सरकार* बताते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। असम और बंगाल की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि असम में चाय बागान मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलती है, जबकि बंगाल में कम है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने पर लगभग पांच लाख नौकरियां दी जाएंगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह लोगों को यह कहकर गुमराह कर रही है कि भाजपा के सत्ता में आने पर मछली-मांस पर रोक लग जाएगी। उन्होंने कहा कि असम में भाजपा सरकार होने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा खुली होने के कारण जनसंख्या संतुलन बदल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की तृणमूल सरकार वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। भाजपा सरकार आने पर इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिनिकी शर्मा मामले में ...

के लिए उचित न्यायालय में जाने का समय मिल गया। खेड़ा ने 7 अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने हैदराबाद का अपना आवासीय पता दर्ज कराया और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी, रिनिकी भुईयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा मुख्यमंत्री के 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए दिए गए चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया था। शर्मा परिवार ने इन दावों को झूठा और मनगढ़ंत बताया। इन आरोपों के बाद, खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिनमें चुनाव के संबंध में झूठे बयान देने के लिए धारा 175, आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित धारा 35 और धोखाधड़ी के लिए धारा 318 शामिल हैं।

हिमंत शर्मा का राहुल ...

वह (राहुल गांधी) यही कहेंगे? बोलने से पहले राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि वह भगवान नहीं हैं। उन्हें मीडिया के सामने अपना पासपोर्ट दिखाना चाहिए, और मैं भी अपनी पत्नी का पासपोर्ट पेश करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई एक सप्ताह की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। साथ ही, असम सरकार द्वारा इस जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर खेड़ा को नोटिस जारी किया गया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने खेड़ा को नोटिस जारी कर असम सरकार द्वारा दायर याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। असम सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि, बेंच ने यह भी कहा कि यदि खेड़ा असम में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश इसमें बाधा नहीं बनेगा। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी के पास भारत, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं और दुबई में उनकी कई आलीशान संपत्तियां हैं, साथ ही अमेरिका के व्योमिंग में उनकी एक कंपनी भी है। शर्मा परिवार ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया है और कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

पोलिंग स्टेशन पर हिंसा ...

अभी बिश्रामगंज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शिकायतकर्ता का दावा है कि घटना वाले दिन विधायक तफज्जल हुसैन अचानक करीब 200 समर्थकों के साथ पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए। इस वजह से वहां तनाव चरम पर पहुंच गया और हालात तेजी से बिगड़ गए। प्राथमिकी में बताया गया है कि उस समय पोलिंग स्टेशन के आसपास बम फेंका गया था। टिपरा मोथा सदस्य ने आरोप लगाया है कि यह हमला मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के इरादे से प्लान के साथ किया गया था। आरोप है कि जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया तो आरोपित वहां से भाग गए। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, घटना के बाद इलाके में और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं। हालांकि, इस घटना पर राजनीतिक हलकों में कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपितों की पहचान करके कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अब, बाढ़ की भविष्यवाणी...

कहा। इस परियोजना का मुख्य आधार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जो बाढ़, चरम मौसम की घटनाओं और यहां तक कि नदी के मार्ग में परिवर्तन की भविष्यवाणी करती है। उपग्रह डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग का उपयोग करके निर्मित यह प्रणाली स्थान-विशिष्ट अलर्ट प्रदान करती है - जिससे किसानों को आपदाओं के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से तैयारी करने में मदद मिलती है। यह पहल पूर्वानुमान से परे जाकर संपूर्ण कृषि चक्र को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास करती है। दूरस्थ गांवों में किए गए जमीनी अध्ययनों से पता चला है कि बुनियादी ढांचे की कमी नहीं, बल्कि सूचना की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। एक किसान को यह तो पता हो सकता है कि क्या उगाना है, लेकिन यह नहीं कि गुणवत्ता वाले बीज कहाँ से मिलेंगेज् हमारी सबसे बड़ी खोज यह थी कि बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि जानकारी ही असली बाधा है, डॉ. मुखोपाध्याय ने कहा। इस कमी को दूर करने के लिए, टीम ने कृषि विकास नामक एक बहुभाषी, ध्वनि-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है, जिसे किसानों के लिए एक डिजिटल साथी के रूप में डिजाइन किया गया है। बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक, यह ऐप फसल संबंधी सुझाव, इनपुट तक पहुंच, बीमा, ऋण और बाजार संपर्क को एकीकृत करता है, जिसमें एमएसपी विवरण और भंडारण सुविधाएं शामिल हैं। यह ऐप प्रधानमंत्री-किसान और कृषि अवसंरचना कोष जैसी सरकारी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर समेकित करता है। लॉन्च होने के एक महीने के भीतर ही ऐप 700 उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर चुका है और प्राप्त फीडबैक के आधार पर इसमें लगातार सुधार किए जा रहे हैं। डॉ. मुखोपाध्याय ने आगे कहा कि अब हमारा ध्यान इसके विस्तार पर है... हमारा लक्ष्य इसे नीतिगत ढांचों के साथ एकीकृत करना और सरकारी एजेंसियों के साथ इसकी पहुंच का विस्तार करना है। प्रौद्योगिकी को जमीनी हकीकतों के साथ मिलाकर, यह पहल पूर्वोत्तर में अधिक लचीली, जानकारीपूर्ण और समावेशी खेती की ओर एक बदलाव का संकेत देती है।

विरोध की लंबी कीमत...

लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। उन्होंने कहा कि हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय मिलकर देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को एक संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वह देश की राजनीति के रूप-स्वरूप को तय करने के साथ देश की दिशा और दशा भी तय करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब, सिर्फ उत्तम प्रकार की रेल, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े... सिर्फ इतने से विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत के नीति निर्धारण में सबका साथ-सबका विकास का मंत्र समाहित हो। देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या देश की नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। हम पहले ही देरी कर चुके हैं, कारण कुछ भी हो, जिम्मेदार कोई भी हो। इसे हमें स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जब से महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद जब-जब चुनाव आया है, महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तब सबने सर्वसम्मति से इसे पारित किया तो यह विषय ही नहीं रहा। मोदी ने कहा कि अगर हम सब साथ आ जाते हैं, तो इतिहास गवाह है, ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश की सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उस यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार होगा और न ही मोदी उसका हकदार होगा। इस लिए जिन किसी को भी इससे राजनीति की बू आ रही है, वो पिछले 30 साल के खुद के परिणामों को देख लें। फायदा उनका भी इसी में है। जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से 25-30 साल पहले, जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया वो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पर पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत कर आईं बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। पहले वो शांत रहती थीं, समझती थीं लेकिन बोलती नहीं थीं। आज वो वोकल हैं। इसलिए आज जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो लाखों बहनें जो पंचायत में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लोगों के सुख-दुख को गहराई से देखा है, वो आंदोलित हैं। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ों और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा और लोकसभा में होती हैं। इसलिए राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते हैं, उनको ये मानकर चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। वो सिर्फ यहां नहीं, वहां भी आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली हैं। जो आज विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी।

नोएडा बवाल : सीमा पार ...

जरिये आई थी। कई संगठन दूर के राज्यों से वॉट्सऐप ग्रुपों को संचालित कर रहे थे। एसटीएफ हिंसा के दौरान बनाए गए 500 से अधिक वीडियो खंगाल रही है। कुछ टेलीग्राम ग्रुप भी श्रमिकों को उकसाने के लिए बनाए गए थे। जांच में तेलंगाना व कर्नाटक से कुछ लोगों की डिजिटल ट्रेल मिली है। सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद बुधवार रात तक करीब 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकतर गिरफ्तारियां कोतवाली फेज वन, फेज टू, सेक्टर-58, सेक्टर-63 और फेज थ्री से हुई हैं। प्रशासनिक अफसर बुधवार को पूरी तरह मुस्तैद रहे। जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार तक ने औद्योगिक सेक्टरों में डेरा डाले रखा। श्रमिकों के रहने वाले गांवों में भी शांति मार्च निकाला गया। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने श्रमिकों से बातचीत कर वेतन वृद्धि की जानकारी दी। उन्होंने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने मजदूर बिगुल दस्ता संगठन के प्रमुख रूपेश राय समेत 18 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यही संगठन उपद्रव के लिए जिम्मेदार है। जांच में पता चला कि इस संगठन के लोग फैक्ट्री एरिया में घूम-घूम कर श्रमिकों को भड़का रहे थे। मानेसर में भी इसी संगठन ने फैक्ट्री में हिंसा करवाई थी। अब लगभग 70 फीसदी उद्योगों में फिर से काम शुरू हो गया है।

हरिवंश का रास का ...

प्रसताव में संजय कुमार झा प्रस्तावक हैं और अनुमोदक उपेंद्र कुशवाहा हैं। पांचवें प्रस्ताव में जयंत चौधरी प्रस्तावक हैं और अनुमोदक मिलिंद मुरली देवड़ा हैं। तय समय यानि 16 अप्रैल, 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक, विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। विपक्ष ने पहले ही ऐलान किया है कि विपक्ष की ओर से उप सभापति चुनाव का बॉयकॉट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जगत प्रकाश नड्डा शुक्रवार को सदन में प्रस्ताव रखेंगे और एस। फांगनोन कोन्याक उसको अनुमोदित करेंगी। इसके बाद प्रस्ताव सदन द्वारा ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। इसके बाद सभापति घोषणा करेंगे कि हरिवंश राज्य सभा के उपसभापति के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद परंपरा के मुताबिक हरिवंश को सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन द्वारा उनको आसन तक ले जाया जाएगा। हरिवंश का बतौर राज्यसभा उपसभापति ये तीसरा कार्यकाल होगा। पहली बार हरिवंश अगस्त 2018 में उपसभापति बने थे। फिर दोबारा सितंबर 2020 मे उपसभापति बने थे। इस बार केंद्र सरकार द्वारा हरिवंश को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सभा के उपसभापति का पद रिक्त होने के बाद चुनाव कराने के लिए शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 की तारीख तय की थी।

कोलकाता के सौ से ज्यादा ...

लागू करने के लिए प्रभावित बूथों में अस्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर जेनरेटर की व्यवस्था की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, सबसे ज्यादा बिजली विहीन बूथ कोलकाता पोर्ट इलाके में पाए गए हैं, जहां 50 से अधिक बूथों में बिजली नहीं है। इससे पहले वहां मतदान कैसे हुआ, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतदान के दिन सुरक्षा कारणों से कई बूथों की खिड़कियां और अतिरिक्त दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे अंदर अंधेरा हो जाता है। इसलिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था जरूरी है, अन्यथा मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि हर बूथ पर पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। डीईओ को अगले कुछ दिनों में इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

कूटनीतिक प्रयासों के...

बना सकता है और उन्हें नष्ट कर सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उसके आर्थिक और समुद्री अधिकार पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते, वह इस रणनीतिक जलमार्ग से पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच, अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखी है। यह नाकाबंदी लगातार तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए घोषणा की है कि कोई भी जहाज यदि ईरान के समर्थन में गतिविधि करेगा या अमेरिकी बलों पर हमला करेगा, तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। उधर, ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका की कार्रवाइयों को उकसाने वाला बताते हुए चेतावनी दी है कि इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी और होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी कदम पहले से ही जटिल स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रस्ताव को एकतरफा और अविवेकपूर्ण करार दिया और चीन तथा रूस के समर्थन की सराहना की।

तुर्की के स्कूल में भीषण...

बुधवार को तुर्की के एक स्कूल में पांच बंदूकों से लैस 14 वर्षीय लड़के ने गोलीबारी की, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद छात्रों के खिड़कियों से कूदकर जान बचाने के कारण अफरा-तफरी मच गई। दक्षिणी प्रांत कहरामनमारास में हुआ यह हमला तुर्की में लगातार दूसरे दिन हुई ऐसी दूसरी घटना है, जिसने उस देश को झकझोर दिया है, जहां स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं दुर्लभ हैं। गृह मंत्री मुस्तफा सिफ्टसी ने नौ मौतों और 13 घायलों की पुष्टि की है, जिनमें से छह आईसीयू में हैं, और तीन की हालत गंभीर है। मंत्री ने हमलावर को 8वीं कक्षा का 14 वर्षीय छात्र बताया। कहरमनमारास प्रांत के गवर्नर मुर्करेम उनलुएर ने दिन में पहले पत्रकारों को बताया कि एक छात्र अपने बैग में बंदूकें लेकर स्कूल आया था, जिनके बारे में हमारा मानना है कि वे उसके पिता की थीं।

आश्रम स्कूल में जहरीला ...

इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मृत छात्रा की पहचान 12 वर्षीय रुपाली बेश्रा के रूप में हुई है, जिसने बारिपदा जिला मुख्य चिकित्सालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, दो दिन पूर्व स्कूल हॉस्टल में भोजन करने के बाद करीब 146 छात्र-छात्राएं उल्टी-दस्त, बुखार और पेट दर्द की शिकायत से बीमार पड़ गए। सभी को पहले रासगोबिंदपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में 60 से अधिक बच्चों को बारिपदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। छात्रा की मौत की खबर फैलते ही अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। रासगोबिंदपुर बाजार के पास सड़क जाम और स्कूल घेराव किया गया। स्थिति बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हो गए। इधर, घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। बिजू जनता दल (बीजेडी) ने छात्रा की मौत के विरोध में शनिवार, 18 अप्रैल को मयूरभंज जिला में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। पार्टी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। बारिपदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां मुआवजा और न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म *एक्स* पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वर्तमान में 60 से अधिक छात्र बारिपदा जिला मुख्य चिकित्सालय में तथा अन्य रासगोबिंदपुर अस्पताल में इलाजरत हैं। डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश बच्चों की हालत अब स्थिर है और उनमें सुधार हो रहा है। प्रशासन ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और भोजन की गुणवत्ता व लापरवाही के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

राज्यों का नहीं घटेगा ...

बातचीत कल रखेंगे लेकिन इस मुद्दे पर वे आज कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उनसे पहले कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। इसके ठीक बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज रात भी इस पूरे विषय पर कोई भ्रांति ना हो इस उद्देश्य से वह संक्षिप्त रूप से अपनी बातचीत रखना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए वर्तमान सीटों में 50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। 543 में 50 प्रतिशत सीटें जोड़ने से आंकड़ा 816 होता है और 850 असल में राउंडअप फिगर है। वर्तमान में भी 543 पूर्ण आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि परिसीमन और सीटों में बढ़ोत्तरी के बाद दक्षिण भारत के राज्यों के वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रतिशत में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होगी और उनका राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रतिशत 7.18 से बढ़कर 7.23 हो जाएगा। इसी तरह से दक्षिण भारत के सभी पांच राज्यों की वर्तमान में 129 लोकसभा सीटें हैं और प्रतिनिधित्व 23.76 प्रतिशत है। यह बढ़कर 195 हो जाएंगी और प्रतिनिधित्व 23.97 प्रतिशत हो जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। वह बताना चाहते हैं कि सरकार ने पहले ही जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है। वर्तमान में घरों की गिनती की जा रही है और इस कारण इससे जुड़े फॉर्म में जाति का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष परिसीमन को लेकर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि अपने लोगों को सरकार इससे जुड़े आयोग में बिठा देगी।

मेघालय : अंग्रेजी के साथ-साथ खासी और गारो आधिकारिक भाषाएं बन गईं

शिलांग। क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अंग्रेजी के साथ-साथ खासी और गारो भाषाओं को भी आधिकारिक दर्जा दिया गया है। यह निर्णय राज्य की भाषा नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है और इसमें मेघालय राज्य भाषा अधिनियम, 2005 को निरस्त करना भी शामिल है। एक बार लागू होने के बाद, यह अध्यादेश सरकारी संचार में खासी और गारो भाषाओं के उपयोग को सक्षम बनाएगा, और प्रशासन, परीक्षाओं और सार्वजनिक मामलों में उनकी भूमिका को धीरे-धीरे विस्तारित करने की योजना है। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा कानूनों को नए ढांचे के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जिनमें मेघालय राज्य विधानमंडल (अंग्रेजी भाषा का निरंतरता) अधिनियम, 1980 में परिवर्तन भी शामिल हैं। इन बदलावों से अंततः विधानसभा के सदस्यों को अंग्रेजी के अलावा खासी और गारो भाषाओं में बोलने और बहस करने की अनुमति मिल जाएगी, हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इस कदम से राज्य स्तरीय परीक्षाओं में इन भाषाओं के उपयोग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यद्यपि इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से होगा, अध्यादेश शासन में खासी और गारो भाषाओं को व्यापक रूप से अपनाने की नींव रखता है। यह निर्णय मेघालय विधानसभा द्वारा पारित उस प्रस्ताव के अनुरूप है जिसमें खासी और गारो समुदायों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। राज्य सरकार का मानना है कि राज्य स्तर पर आधिकारिक मान्यता प्रदान करने से राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की उसकी मांग मजबूत होगी। कैबिनेट के फैसले के बाद, मुख्यमंत्री ने खासी लेखक समाज के सदस्यों को घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए एक बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने और उन्हें आठवीं अनुसूची में शामिल करने के महत्व के बारे में एक मजबूत संदेश देता है। सांगमा ने कहा कि खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देने की मांग वर्षों से चली आ रही थी, और उन्होंने मंत्रिमंडल के इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकारी संचार और परीक्षाओं में पूर्ण कार्यान्वयन में समय लगेगा, लेकिन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आगामी शरद सत्र में विधायकों द्वारा इन भाषाओं का उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है, और आशा व्यक्त की कि नए विधानसभा भवन में होने वाले भविष्य के सत्रों में खासी और गारो भाषाओं में बहस आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने में खासी लेखक समाज का समर्थन मांगा और इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्णय अपने इच्छित प्रभाव को प्राप्त करे। उन्होंने भाषाओं की मान्यता के लिए लगातार प्रयास करने हेतु खासी लेखक समाज और अचिक साहित्य समाज दोनों को श्रेय दिया। बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग और स्नियावभलांग धर भी उपस्थित थे।

सांसद, मंत्री, विधायक एवं भाजपा के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की 50 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल में करेगी प्रचार

गुवाहाटी (हिंस)। आसन्न विधानसभा चुनाव के लिए असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 50 सदस्यों वाली टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंच गयी। 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए असम की इस टीम का उद्देश्य राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करना है। असम भाजपा के प्रवक्ता प्रांजल कलिता ने गुरुवार को इसकी जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी। उल्लेखनीय है कि, गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा पहले ही पश्चिम बंगाल में उपस्थित होकर कूचबिहार, कालसिनी और फांसीदेओवा विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा टीम में कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका, जयंत मल्लबरुवा, रंजीत कुमार दास, बिमल बोरा, डॉ. रनोज पेगु, रूपेश गोवाला, कृपनाथ मल्ल, राजद्वीप रॉय, कृष्णेंदु पाल, कौशिक राय और सांसद परिमल शुक्ल बैद्य के साथ-साथ कई विधायक और राज्य स्तरीय नेता पहले ही पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में सक्रिय हो चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता ने बताया है कि देश में चल रहे चार राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र के विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल के चुनाव भाजपा दल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही कई राज्य और राष्ट्रीय मीडिया ने एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनमत व्यक्त किया है और इसके समानांतर कई मीडिया ने पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की संभावनाओं को व्यक्त किया है।

अल्फा (स्वा) से कथित संबंधों के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

चराईदेव (हिंस)। चराईदेव जिला मुख्यालय सोनारी पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-स्वाधीन (अल्फा-स्वा) से कथित संबंधों के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान वांग उर्फ नोनी के रूप में हुई है। उसे एक सुरक्षा अभियान के दौरान असम के चराइदेव जिले के सोनारी उपमंडल के नामतोला इलाके से पकड़ा गया। अधिकारियों को संदेह है कि वह अल्फा (स्वा) के लिए एक *लिंकमैन* (सहायक) के तौर पर काम कर रहा था और उनके बीच संचार या लॉजिस्टिक सहायता (साजो-सामान की मदद) में मदद कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच जारी होने का हवाला देते हुए अभियान से जुड़ी और अधिक जानकारी साझा नहीं की है। गिरफ्तार व्यक्ति से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, ताकि उसकी संलिप्तता की सीमा और नेटवर्क से उसके किसी भी संभावित जुड़ाव का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले, तिनसुकिया पुलिस ने जिले के अलग-अलग हिस्सों से अल्फा (स्वा) के सात कथित लिंकमैनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति कथित तौर पर लंबे समय से अल्फा (स्वा) के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान में शामिल था। ये गिरफ्तारियां कई जगहों पर अलग-अलग अभियानों के दौरान की गईं। पुलिस ने बताया कि आरोपी फिलहाल चल रही जांच के तहत पूछताछ के घेरे में है, ताकि उनकी संलिप्तता की सीमा और नेटवर्क के भीतर उनके संभावित संपर्कों का पता लगाया जा सके।

राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने साइकिल से पहुंचे तेरेस गोवाला

गुवाहाटी/नई दिल्ली (हिंस)। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद तेरेस गोवाला ने सादगी और अपने अतीत की यादों को ताजा करते हुए संसद भवन पहुंचने के लिए साइकिल का सहारा लिया। उनके इस अनोखे अंदाज ने आज सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तेरेस गोवाला ने दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया।

आमतौर पर जहां नेता वाहन काफिले के साथ संसद पहुंचते हैं, वहीं उनका यह कदम अलग और खास नजर आया। उनकी इस पहल को सादगी और जड़ों से जुड़े रहने का संदेश माना जा रहा है। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में पहुंचकर शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कीं।

लामडिंग रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई कर्मचारियों ने किया विरोध-प्रदर्शन

होजाई (हिंस)। लामडिंग रेलवे जंक्शन के स्थायी सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। गुरुवार सुबह ही लामडिंग रेलवे जंक्शन परिसर में विरोध प्ररदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिलायबल कंक्रीट कॉर्पोरेशन नामक संस्था की देखरेख में लामडिंग में सफाई का काम चलने की बात सामने आई है। आरोप लगाया गया है कि काफी समय से सफाई कर्मचारी लामडिंग रेलवे जंक्शन परिसर की सफाई अपने हाथों से करते आ रहे हैं और आम जनता की सुविधा के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनके हक से वंचित किया जा रहा है। आरोप है कि वे वर्षों से 9-10 हजार रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में 16 हजार रुपए जमा किये जाते हैं। वे यह भी शिकायत करते हैं कि उन्हें मिलने वाले मेडिकल लाभ, पीए आदि से भी वंचित किया गया है। यह गंभीर आरोप ठेकेदार सुषांत पाल के खिलाफ लगाए गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने बार-बार शिकायत की है कि हर महीने उन्हें उनके बैंक खाते में 16 हजार रुपए आने का संदेश मिलता है, लेकिन कर्मचारी हर

महीने हाथ में सिर्फ 9-10 हजार रुपए ही पाते हैं। शेष रकम ठेकेदार द्वारा हड़पे जाने का आरोप लगाए गए हैं। गरीब तथा समाज की गंदगी सामग्रियों की साफ-सफाई वे अपने हाथों से करने वाले इन सफाई कर्मचारियों के हक का धन अचानक गायब हो जाता है। उन्होंने कहा है कि हमारी शिकायतों के बाद भी क्या रेलवे प्रशासन ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा?

असम प्रदेश भाजपा ने एक देश-एक चुनाव समेत तीनों विधेयकों का किया स्वागत

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार से आरंभ तीन दिवसीय संसद के विशेष सत्र के दौरान उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। प्रदेश भाजपा ने कहा है कि इस सत्र में एक देश एक चुनाव, देशभर में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण के साथ-साथ संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षण- *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* विषय पर तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए हैं। इसी के बीच 207 मतों के साथ लोकसभा में *एक देश-एक चुनाव* विधेयक पारित होने की जानकारी पार्टी के प्रवक्ता प्रांजल कलिता द्वारा दी गई। संविधान संशोधन के माध्यम से संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई अर्थात 33 प्रतिशत सीटें सुरक्षित करने के निर्णय को, जो देश की महिला शक्ति को अधिक गति देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा लिया गया है, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और दरंग-उदालगुड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिलीप सैकिया ने स्वागत किया।

सतिया में केंद्रीय 93वें बोहाग मेले का शुभारंभ

विश्वनाथ (विभास)। सतिया में 93वां केंद्रीय बोहाग मेला का शुभारंभ किया गया। यह मेला असम के त्योहार रंगाली बिहू के पहले दिन आयोजित किया गया। बिहू मेले का झंडा उत्सव समिति के अध्यक्ष भव सैकिया द्वारा सुबह 9 बजे आधिकारिक तौर पर फहराया गया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त सचिव हेमांग हजारिका ने किया। इसके बाद एक आध्यात्मिक माहौल में बिहू मेले की आधारशिला रखी गई। इस कार्यक्रम में बहुत से गणमान्य लोगों ने भाग लिया। दोपहर को मेले में उन विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने असमिया समाज, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। इस क्षेत्र की 18 गणमान्य हस्तियों को केंद्रीय बिहू उत्सव समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इनमें सतिया के जाना पहचाना बिहुवा दल मोरनोई पोरिया बिहुवा दल ने बिहू नाच गान से माहौल में चार चांद लगा दिया।

तीवा जनजाति का कृषि आधारित लखमी आदरा उत्सव का आयोजन 22 से

मोरीगांव (हिंस)। प्रत्येक पांच वर्ष बाद तीवा जनजाति का कृषि आधारित उत्सव लुखुमी यांगली यानी लखमी आदरा उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार भी तीवा जनजातियों का दिल कहा जाने वाला जिला कार्बी आंग्लांग के उमसुआई के आमसांग पिनुंग में तीन दिवसीय कार्यक्रमों के साथ आगामी 22, 23 और 24 अप्रैल को विशेष कृषि आधारित उत्सव संपन्न होगा। इस बीच लखमी आदरा की तैयारी गांववालों ने पहले ही शुरू कर दी है। पहाड़ और मैदानी इलाकों में रहने वाले तीवा लोगों के साथ सभी स्तर के लोगों को इस उत्सव में शामिल होने के लिए आयोजन समिति ने आमंत्रित किया है। जागीरोड के ऐतिहासिक गोभा देवराजा चारीभाई देवशाल शिवस्थान में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इस बात की सूचना दी। संवाददाता सम्मेलन में गोवा राजा दीपसिंग देवराजा, गोभा देवराजा राजदरबार प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नगेन कुंवर, सचिव जुरसिंग बरदलै, सदस्य द्विपेन कुंवर, अमर बरदलै, कार्बी आंग्लांग जिले के उमसुआई के आमसांग पिनुंग गांव के लिमचिंग पोमा, सानजाई माशलाई आदि कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान बताया गया कि इस बार का उत्सव काफी आकर्षक और शानदार होगा। इसकी तैयारी अपने अंतिम चरण में है।

स्टॉकहोम पुलिस ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया

इंफाल। सुरक्षा बलों और सैन्य बलों ने रविवार को पूरे राज्य में अपनी कार्रवाई तेज कर दी, जिसके परिणामस्वरूप समनवित अभियान चलाया गया और गिरफ्तारियों, जब्ती और उग्रवादी संगठनों को नष्ट कर दिया गया। चोरीचंदपुर जिले में सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियमित जांच के दौरान एक वाहन को रोके जाने के बाद रेंगाईकाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एस मोल्डुंग के नागमखोमांग हाओकिप और लैंगनोम गांव के लेटमिनथांग हाओकिप के रूप में हुई है। उनके पास से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें वाहन भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, इन दोनों में कथित तौर पर सीलमैट ब्रिज पर हुई शूटिंग की पिछली घटना शामिल थी।

यूपीपीएल नेता राजू कुमार नार्जरी के घर चोरी

कोकराझाड़ (विभास)। एक तरफ जहां पूरा परिवार शोक में डूबा था, वहीं दूसरी ओर अपराधियों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दीं। यूपीपीएल के महासचिव (प्रशासन) राजू कुमार नार्जरी के चंद्रपाड़ा स्थित आवास पर बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू कुमार नार्जरी के भाई का कल निधन हो गया था। इस दुखद घड़ी में वे अपने पूरे परिवार के साथ पैतृक गांव वाले घर पर थे। घर सूना पाकर चोरों ने चंद्रपाड़ा स्थित उनके आवास को निशाना बनाया। चोरी हुए सामान में शामिल हैं, लगभग 30 ग्राम सोने के आभूषण। एक लैपटॉप और अन्य कीमती सामान। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। इस संबंध में संबंधित थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश जारी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। शोक संतप्त परिवार के अनुपस्थिति में हुई इस चोरी की कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। लोगों का कहना है कि यह केवल एक चोरी नहीं, बल्कि *मानवता का संकट* है कि अपराधी अब शोक मना रहे परिवारों को भी नहीं बख्श रहे हैं। क्षेत्र के विभिन्न संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है।

उपलब्धि

श्रैयश बांठिया ने सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सभी विषयों में लेटर मार्क्स अर्जित किए हैं। वह मानस वैली अकादमी, बरपेटा रोड के मेधावी छात्र हैं। श्रैयश बरपेटारोड निवासी इंद्रचंद बांठिया एवं श्रीमती कमला देवी बांठिया के पौत्र तथा मनीष बांठिया एवं श्रीमती ममता बांठिया के सुपुत्र हैं। हम उन्हें इस उत्कृष्ट सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करते हैं।

गुप्तकाशी विश्वनाथ घाट में 442 साल पुरानी परंपरा गोसाईं भ्रमण धूमधाम से मनी

विश्वनाथ (विभास)। समग्र राज्य में रंगाली बिहू के तीसरे दिन गोसाईं बिहू पालन के साथ आज बिश्वनाथ घाट में गोसाईं फुरोवा उत्सव हर साल की तरह बिश्वनाथ में मनाया जा रहा है। यह परंपरा अहोम राजा गदाधर सिंह के समय से चली आ रही है। गुप्तकाशी विश्वनाथ घाट में 442 साल पुरानी परंपरा मुख्य मंदिर बिश्वनाथ बाबा मंदिर है, जहां गोसाईं को नहलाया जाता है और पानीभड़ाल के काई ढाप मैदा में ले जाया जाता है। शाम को पुन: गोसाईं को वापस मुख्य मंदिर में लाया जाता है। उन्हें ढोल पर रखकर अलवान पर रखा जाता है और जुलूस के दौरान, गृहस्थ अपने-अपने घर के आंगन में पूजा करते हैं और गोसाईं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन जनता बिहू नृत्य गायन के आनंद से उल्लासित होकर हर्षोल्लास पूर्वक यह उत्सव मनाते हैं। इधर पानीभड़ाल के काईढाप मैदान में एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय विश्वनाथ का दसवीं का परिणाम शत-प्रतिशत

सभी 75 विद्यार्थी डिस्टिंक्शन अंक से हुए उत्तीर्ण

विश्वनाथ (विभास)। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय विश्वनाथ असम ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहराया है। 100 प्रतिशत परीक्षा परिणाम के साथ विद्यालय के समस्त 78 छात्रों का प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना संस्था की शैक्षणिक गुणवत्ता का जीवंत प्रमाण है। इस ऐतिहासिक सफलता की नींव में विद्यालय के प्राचार्य महोदय का कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नेतृत्व सर्वोपरि रहा है। उनके मार्गदर्शन में विद्यालय ने कई प्रभावी कदम उठाए। प्राचार्य महोदय ने विद्यालय में एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जहां अनुशासन और नवाचार का संगम है। साथ ही उन्होंने न केवल प्रशासनिक कार्यों को संभाला, बल्कि स्वयं प्रत्येक छात्र की प्रगति रिपोर्ट का नियमित अवलोकन भी किया, जिससे छात्रों में निरंतर सुधार की प्रेरणा बनी रही। इसी के साथ बोर्ड परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए समय-समय पर प्रेरणादायक सत्रों का आयोजन करना उनकी विशेष पहल रही। विद्यालय के शिक्षक वृंद इस सफलता के वास्तविक सारथी हैं। उनकी कर्तव्यनिष्ठा ने ही इस परिणाम को संभव बनाया है। शिक्षकों ने नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त *रेमेडियल* (उपचारात्मक) कक्षाओं के माध्यम से कमजोर छात्रों की कमियों को दूर किया। सामाजिक विज्ञान में 14, असमिया में 03, हिंदी में 01 और अंग्रेजी में 8 छात्रों का 100 अंक प्राप्त करना शिक्षकों की गहन शिक्षण पद्धति को दर्शाता है। शिक्षकों ने केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि छात्रों के लिए एक *मेंटर* (मार्गदर्शक) के रूप में कार्य किया, जिससे 75 छात्रों ने *डिस्टिंक्शन* प्राप्त की। विद्यालय की मेरिट सूची में शीर्ष पांच स्थानों पर छात्राओं का वर्चस्व रहा है। श्रुति व्यंजना (98.6 प्रतिशत), विद्यालय की टॉपर बनकर उन्होंने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दीया देवी (98.0 प्रतिशत), दूसरे स्थान पर रहते हुए शानदार सफलता अर्जित की। छाया गोगोई (97.8 प्रतिशत), सूक्ष्म अंतर से तीसरे स्थान पर रहीं। चिरश्रुति बोराह (97.6 प्रतिशत), चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई। सुहान अली (96.8 प्रतिशत), शीर्ष पांच की सूची में अपनी जगह सुरक्षित की। *पीएम श्री* स्कूल के रूप में मिलने वाली आधुनिक सुविधाओं का प्राचार्य और शिक्षकों ने सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया। स्मार्ट क्लास और आधुनिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से कठिन विषयों को सरल बनाकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। पीएम श्री जेएनवी विश्वनाथ की यह उपलब्धि प्राचार्य की प्रशासनिक कार्यकुशलता और शिक्षकों के निस्वार्थ सेवा भाव का सुखद परिणाम है। यह गौरव गाथा आने वाले वर्षों में नए छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। विद्यालय प्रबंधन इन सभी योद्धाओं को उनकी सामूहिक जीत पर नमन करता है।

धूबड़ी पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ ड्रग्स माफिया मोइइनुद्दीन को किया गरफ्तार

धुबड़ी। (विभास)। धुबड़ी पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कुंतीर चर में पुलिस ने अभियान चलाकर नशीले पदार्थों के साथ कुख्यात ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया। पकड़े गए ड्रग्स माफिया की पहचान मोइनुद्दीन शेख के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी मोइनुद्दीन को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस उससे आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ कर रही है।

संपादकीय

उम्मीदों का गलियारा

निस्संदेह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भारत के संरचनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। जो राष्ट्रीय राजधानी और उत्तराखंड के प्रवेश द्वार के बीच यात्रा के समय को छह घंटे से घटाकर ढाई घंटे करने का वायदा करता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित यह एक्सप्रेसवे उत्तराखंड ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा देगा। इंजीनियरिंग की विशिष्ट उपलब्धि से बढ़कर, परियोजना राजमार्गों की कल्पना में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। जो महज एक सड़क ही नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों, बाजारों और अवसरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा भी है। इस राजमार्ग के बनने से जहां परंपरागत मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी से देहरादून और मसूरी आदि अन्य हिल स्टेशनों में पर्यटन बढ़ेगा। निस्संदेह, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पश्चिमी उ.प्र. के सहारनपुर व शामली जैसे जनपदों, जिन्हें विकास की दौड़ में पर्याप्त अवसर नहीं मिले, उनके लिये भी वरदान साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि खाद्यान्न, भंडारण और रियल एस्टेट में भी इस परियोजना के लाभ नजर आएंगे। कह सकते हैं कि यह एक्सप्रेसवे भारतमाला जैसी परियोजनाओं के तहत एकीकृत, उच्च गति वाले गलियारों के लिये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्यों को पूरा करता है। वहीं दूसरी ओर इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विकास और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। प्रतिष्ठित राजाजी पार्क क्षेत्र से गुजरने वाला यह ऊंचा वन्यजीव गलियारा, जिसमें वन्य जीवों के लिये अंडरपास बनाये गए हैं ताकि उनके प्राकृतिक आवागमन मार्गों में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो। जो इस मान्यता की कसौटी पर खरा उतरता है कि विकास के बुनियादी ढांचे को प्रकृति के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। aहाल के वर्षों में देश की विभिन्न बड़ी विकास योजनाओं वाले क्षेत्रों में वन्य जीवों और मनुष्य के बीच जो संघर्ष बढ़ा है, वो विकास को पर्यावरण व वन्यजीवों के अधिवास के अनुकूल ढालने की जरूरत बताता है। कर्नाटक के हाथी गलियारे- जो बांदीपुर,नागरहोल और आसपास के जंगलों को जोड़ते हैं, दर्शाते हैं कि कि कैसे संपर्क मार्गों से वन्य जीवों के प्रवास-मार्ग की सुरक्षा होती है। जिससे मानव व वन्य जीवों का संघर्ष कम होता है। ऐसे में यदि दिल्ली-देहरादून राजमार्ग में अभिनव प्रयास प्रभावी साबित होते हैं, तो यह नया एक्सप्रेसवे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भविष्य की परियोजना के लिए एक आदर्श साबित हो सकता है। हालांकि, इस राजमार्ग को लेकर कुछ चिंताएं अभी बाकी हैं। राजमार्ग को पूरा करने के दौरान अंतिम समय में निर्माण कार्यों में किए गए सुधार और इसमें पहले हुई कुछ देरी की रिपोर्टों से कार्य निष्पादन की गुणवत्ता व समय सीमा के दबाव को लेकर सवाल भी उठे हैं। निस्संदेह, किसी संरचना के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन उद्घाटन की समय सीमा से नहीं बल्कि उसकी मजबूती, सुरक्षा उपायों और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर ही होना चाहिए। अंततः यह एक्सप्रेसवे आशा और सावधानी दोनों का ही पर्याय है। निर्विवाद रूप से यह भारत की तेज और स्मार्ट निर्माण की महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। इसके साथ ही उच्च मानकों की कसौटी पर खरा उतरने और जवाबदेही की जरूरत को भी रेखांकित करता है। निर्विवाद रूप से इस महत्वाकांक्षी परियोजना की वास्तविक सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि यह पारिस्थितिक और संरचनात्मक गुणवत्ता से समझौता किए बिना दक्षता को बनाये रखे। इसके अलावा पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता और पर्यटन के दबाव से भूगर्भीय संवेदनशीलता की भी रक्षा हो। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से भूस्खलन व पर्यटकों का दबाव झेल रहे हिमालयी राज्यों में पर्यटन प्रकृति व स्थानीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। आने वाले दिनों में दिल्ली-देहरादून राजमार्ग उत्तराखंड के चारधाम यात्रा को भी गति देगा, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से विस्तार होना निश्चित है। वहीं चीन से मिलने वाली किसी चुनौती से निपटने में सेना की गतिशीलता, रसद व सैन्य आपूर्ति में भी यह राजमार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।

राष्ट्रीय राजधानी और उत्तराखंड के प्रवेश द्वार के बीच यात्रा के समय को छह घंटे से घटाकर ढाई घंटे करने का वायदा करता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित यह एक्सप्रेसवे उत्तराखंड ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा देगा। इंजीनियरिंग की विशिष्ट उपलब्धि से बढ़कर, परियोजना राजमार्गों की कल्पना में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है। जो महज एक सड़क ही नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों, बाजारों और अवसरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारा भी है। इस राजमार्ग के बनने से जहां परंपरागत मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी से देहरादून और मसूरी आदि अन्य हिल स्टेशनों में पर्यटन बढ़ेगा। निस्संदेह, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पश्चिमी उ.प्र. के सहारनपुर व शामली जैसे जनपदों, जिन्हें विकास की दौड़ में पर्याप्त अवसर नहीं मिले, उनके लिये भी वरदान साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि खाद्यान्न, भंडारण और रियल एस्टेट में भी इस परियोजना के लाभ नजर आएंगे। कह सकते हैं कि यह एक्सप्रेसवे भारतमाला जैसी परियोजनाओं के तहत एकीकृत, उच्च गति वाले गलियारों के लिये केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्यों को पूरा करता है।

राजनीतिक विश्लेषण यदि हम इस प्रश्न की जड़ों में जाएँ, तो असमान प्रतिनिधित्व की समस्या नई नहीं है

नारी शक्ति वन्दन अधिनियमः प्रतिनिधित्व और क्रियान्वयन की चुनौती

डॉ ब्रजेश कुमार मिश्र

भारतीय समाज में नारी सदैव आदरणीय रही है किन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि इन आदर्शों के बावजूद वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उसकी भागीदारी लम्बे समय तक सीमित रही है। यही विरोधाभास भारतीय लोकतन्त्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ एक ओर संविधान ने समानता का अधिकार प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत कम बना रहा जबकि दुनिया के कई देशों जैसे बांग्लादेश (14%), पाकिस्तान (17%) औरनेपाल (33%) में महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण है। इसी तरहरवांडा (30%), तंजानियाऔरयुगांडामें भी विशेष आरक्षण अथवा कोटा व्यवस्था लागू है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वन्दन अधिनियम)इस ऐतिहासिक असन्तुलन को दूर करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित पहल के रूप में सामने आया।

कामायनी के श्रद्धा सर्ग में जयशंकर प्रसाद ने नारी की चेतना को इंगित करते हुए लिखा है "नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास-रजत-नग-पग तल में,पीयूष-स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।" अर्थात्नारी केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है, जो अपने स्नेह, करुणा और संवेदनशीलता से जीवन को सुन्दर और सन्तुलित बनाती है। भारतीय समाज में नारी सदैव आदरणीय रही है किन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि इन आदर्शों के बावजूद वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उसकी भागीदारी लम्बे समय तक सीमित रही है। यही विरोधाभास भारतीय लोकतन्त्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ एक ओर संविधान ने समानता का अधिकार प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत कम बना रहा जबकि दुनिया के कई देशों जैसे बांग्लादेश (14%), पाकिस्तान (17%) औरनेपाल (33%) में महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण है। इसी तरहरवांडा (30%), तंजानियाऔरयुगांडामें भी विशेष आरक्षण अथवा कोटा व्यवस्था लागू है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वन्दन अधिनियम)इस ऐतिहासिक असन्तुलन को दूर करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित पहल के रूप में सामने आया। 28 सितम्बर 2023 को कानून बनने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं फिर भी यह अपनी मूर्तता की बाट जोह रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार 16–18 अप्रैल के मध्य संसद का विशेष सत्र बुला रही है, लेकिन सवाल यह है कि अब तक सरकार ने इस सन्दर्भ में प्रयास क्यों नही किया, सरकार की अग्रिम योजना क्या है और इस कानून के लागू हो जाने के बाद क्या बदलाव होगा, ये ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं जिन्हे संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं के आलोक में समझा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषण यदि हम इस प्रश्न की जड़ों में जाएँ, तो असमान प्रतिनिधित्व की समस्या नई नहीं है। संविधान सभा, जिसने स्वतन्त्र भारत के लोकतान्त्रिक ढाँचे की रचना की, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त सीमित थी,कुल सदस्यों में मात्र4–5 प्रतिशत (लगभग 15 महिलाएँ)। यह आँकड़ा दर्शाता है कि प्रारम्भिक स्तर पर ही महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति कम थी। इसके बावजूद, संविधान निर्माताओं ने समानता के आदर्शों को अत्यन्त महत्त्व दिया।अनुच्छेद 14विधि के समक्ष समानता औरअनुच्छेद 15लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है बावजूद इसके अनुच्छेद 15(3) में राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई। स्पष्ट है कि संवैधानिक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण की नींव मजबूत रखी गई थी लेकिन व्यवहारिक राजनीति में यह समानता परिलक्षित नहीं हो सकी। इस दिशा में पहला वास्तविक और प्रभावी हस्तक्षेप 1992–93 के 73वें और 74वें

संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। इन संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देते हुए महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया(बिहार सबसे पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बढ़ाकर50% किया, इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों ने भी स्थानीय निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू किया)। इस प्रयोग ने न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि महिला नेतृत्व शासन को अधिक संवेदनशील, समावेशी और जनकल्याणकारी बना सकता है। यह अनुभव इस बात का ठोस प्रमाण था कि यदि अवसर मिले, तो महिलाएँ प्रभावी राजनीतिक भूमिका निभा सकती हैं। इसके बावजूद, संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की राह आसान नहीं रही। 1990 के दशक से लेकर 2010 तक यह विधेयक बार-बार संसद में पेश किया गया1996, 1998, 1999, 2003 और 2008लेकिन हर बार यह राजनीतिक असहमति के कारण अटक गया। 2010 में राज्यसभा से पारित होने के बावजूद यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इस विफलता के पीछे कई कारण थेसबसे प्रमुखOBC महिलाओं के लिए अलग उप-कोटा की मांग, पुरुष सांसदों का विरोध, और राजनीतिक दलों के बीच सहमति का अभाव। यह स्पष्ट करता है कि महिला प्रतिनिधित्व का प्रश्न केवल सामाजिक न्याय का नहीं, बल्कि सत्ता-साझेदारी का भी प्रश्न है। संवैधानिक व्यवस्था में पहले से ही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के कुछ प्रावधान मौजूद हैं।अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करते हैं, जबकिअनुच्छेद 334इन आरक्षणों की समय-सीमा निर्धारित करता है। महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 (106 वां संशोधन) ने इसी ढाँचे को आगे बढ़ाते हुए संविधान मेंअनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़कर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है,

हालाँकि, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता और साथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका क्रियान्वयन तन्त्र है। अधिनियम के अनुसार, यह आरक्षणजनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होगा। इस प्रकार एक ओर जहाँ यह ऐतिहासिक कदम है, वहीं दूसरी ओर इसे लागू करने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है जिससे इसका प्रभाव कमजोर होने की सम्भावना है। अब सवाल यह है कि अब तक सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर पायी है? इसके पीछे कारण है कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया लम्बित रही, जिससे क्रियान्वयन टलता गया; अब संशोधन के माध्यम से इसे 2029 से पहले लागू करने की तैयारी है। इसी कारण विशेष सत्र आहूत हो रहा है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए इसमें संशोधन करने की योजना बनाई जा रही है ताकि इसे लम्बित जनगणना से अलग कर समय से लागू किया जा सके। प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ा कर 816करने और उनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षितकरने का विचार है। यह आरक्षण वर्टिकल मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें SC और ST श्रेणियों के भीतर भी महिलाओं को उप-आरक्षण मिलेगा। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर करने का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार एक व्यापक विधायी पैकेज तैयार कर रही है, जिसमें संविधान संशोधन, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेशों में आरक्षण लागू करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य सीटों में वृद्धि कर महिलाओं के लिए स्थान सुनिश्चित करना है। वर्तमान व्यवस्था में देरी के कारण यह 2034 तक टल सकता था, जिसे सरकार अब 2029 तक लागू करना चाहती है। सरकार के अपने जो भी तर्क हों लेकिन उन पर राजनीति करने का आरोप लग सकता है, क्योंकि यदि परिसीमन 2011 के आंकड़ों पर आधारित होता है, तो वर्तमान जनसंख्या संरचना को पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित नहीं किया जा सकेगा जिससे प्रतिनिधित्व में असन्तुलन उत्पन्न हो सकता है। विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सापेक्ष प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका है जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का प्रभाव बढ़ सकता है। सारतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संशोधन, सीट वृद्धि और 2011 आधारित परिसीमन जैसे कदम उठाकर प्रक्रिया को तेज करने का जो प्रयास है, वह राजनीतिक इच्छाशक्ति का संकेत है, किन्तु इसके साथ प्रतिनिधित्व के सन्तुलन और व्यापक सहमति की चुनौती भी जुड़ी हुई है। इस पहल को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावित संशोधनों को पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए, परिसीमन में क्षेत्रीय सन्तुलन का ध्यान रखा जाए, सभी दलों को साथ लेकर सहमति बनाई जाए तथा क्रियान्वयन की स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाए ताकि 2029 तक महिला आरक्षण वास्तविक रूप में लागू हो सके।

देश | दुनीया से

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही विकास की कुंजी

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसके प्राकृतिक संसाधनों, भौतिक विकास या आर्थिक प्रगति में नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा व्यवस्था में निहित होती है। शिक्षा वह सुदृढ़ आधार है, जिस पर एक सशक्त, संवेदनशील और जागरूक समाज का निर्माण होता है। यह केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों को आकार देने वाली सतत प्रक्रिया है। इसलिए यह उक्ति आज भी प्रासंगिक है कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों और शिक्षकों में झलकता है। भारतीय परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का समावेश रहा है। गुरुकुल प्रणाली से लेकर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तक, शिक्षा ने समाज को नई दिशा देने का कार्य किया है। आज जब वैश्वीकरण, तकनीकी क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो चुकी है, तब शिक्षा की भूमिका और अधिक व्यापक तथा बहुआयामी हो गई है। अब शिक्षा केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं, बल्कि नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन और जीवन कौशल विकसित करने का माध्यम बन चुकी है। स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल के अभियानों के बाद राज्य को 'पूर्ण साक्षर' घोषित किया जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वर्तमान में प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 99.30 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत (लगभग 77.80 प्रतिशत) से काफी अधिक है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और सरकारी कार्यकुशलता का सुपरिणाम है। त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद हिमाचल का इस श्रेणी में आना उसकी शैक्षिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का विस्तार संस्थागत विकास के रूप में भी स्पष्ट दिखाई देता है। आईआईटी मंडी, एनआईटी हमीरपुर, एनआईएफटी कांगड़ा और सीएसआईआर पालमपुर जैसे संस्थानों ने हिमाचल को राष्ट्रीय शैक्षिक मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। इसी क्रम में 150 से अधिक सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। चंबा के किलाड़ और मंडी के जंजैहली जैसे क्षेत्रों में छात्र नामांकन में 90 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। शिमला, किन्नौर, सिरमौर और लाहुल-स्पीति के विभिन्न स्कूलों में भी 20 से 50 प्रतिशत तक नामांकन बढ़ा है, जो सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत है। गरली जैसे विद्यालयों में एक सप्ताह के भीतर 344 से अधिक छात्रों का प्रवेश इस परिवर्तन का सुखद उदाहरण है। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1 मार्च 2026 से स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। यह स्पष्ट

शिक्षा वह सुदृढ़ आधार है, जिस पर एक सशक्त, संवेदनशील और जागरूक समाज का निर्माण होता है। यह केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों को आकार देने वाली सतत प्रक्रिया है। इसलिए यह उक्ति आज भी प्रासंगिक है कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसके विद्यालयों और शिक्षकों में झलकता है। भारतीय परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का समावेश रहा है।

करता है कि जब सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता, संसाधन और भरोसे का वातावरण बनता है, तो अभिभावक निजी स्कूलों के बजाय सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता देने लगते हैं। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शिक्षा को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद कई गंभीर चुनौतियां भी सामने हैं। सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों के रिक्त पदों की है। कई विद्यालय आज भी एक या दो शिक्षकों के सहारे संचालित हो रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। शिक्षक-छात्र अनुपात को संतुलित करने के लिए त्वरित और प्रभावी नियुक्तियां आवश्यक हैं। कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के विलय का निर्णय संसाधनों के बेहतर उपयोग की दृष्टि से तर्कसंगत है। संयुक्त परिवारों के विघटन और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के कारण बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में विद्यालय और शिक्षक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक व्यावहारिक, तकनीकी और मूल्य आधारित बनाना होगा। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों बारे शिक्षित करना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। शिक्षा को परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण से निकालकर जीवन कौशल, रचनात्मकता और नैतिक मूल्यों से जोड़ना होगा। छात्रों को अच्छी संगति, व्यावहारिक जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, मीडिया समझ और कौशल करियर शिक्षा से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। निजी स्कूलों की बढ़ती फीस भी एक गंभीर चिंता का विषय है, जो मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है। यूनेस्को की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 27.3 करोड़ बच्चे और युवा अब भी शिक्षा से वंचित हैं, वहीं भारत की शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में गिनी जाती है, जो 14 लाख से अधिक विद्यालयों और करीब 1300 विश्वविद्यालयों के जरिए 24.69 करोड़ विद्यार्थियों तक पहुंच बनाती है, किंतु 65.3 फीसदी महाविद्यालयों का निजीकरण और शिक्षा पर मात्र 4 प्रतिशत सार्वजनिक व्यय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 6 प्रतिशत लक्ष्य से पीछे रहकर इसकी संरचनात्मक चुनौतियों को उजागर करता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2025 को जारी की गई नवीनतम एकीकृत जिला सूचना प्रणाली फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई) रिपोर्ट के अनुसार देश में अब 14.71 लाख से अधिक स्कूलों में 10122420 शिक्षक हैं, जो लगभग 23.29 करोड़ छात्र-छात्राओं को राष्ट्र निर्माण हेतु तैयार कर रहे हैं। इस बार केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा हेतु 1.39 लाख करोड़ आवंटन से एआई, स्किलिंग और डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। 21वीं सदी शिक्षा का लक्ष्य तकनीकी दक्षता, मानसिक संतुलन, आलोचनात्मक सोच और समावेशी, कौशल-आधारित, आजीवन सीखने वाली पीढ़ी बनाना है। इसके लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक निवेश और बजट का प्रावधान करने के साथ-साथ समर्पित, प्रशिक्षित और चरित्रवान शिक्षकों की जमात तैयार करनी होगी। यदि हम वास्तव में एक विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

कुछ | अलग

हमने जमाना बदल दिया

लीजिए इस बार फिर वही हुआ, जिसकी हमें उम्मीद भी न थी। उन्होंने कहा था, बहुत हो गया यह दकियानूसीपन। वही बात का बतंगड़ बनाना। वही बातूनी उपहारों के साथ उपलब्धियों के मिथ्या आंकड़े परोस देना। जेबें भरी होने का एहसास दे रहे वही उनदन गोपाल। भविष्य के सुनहरे सपने दिखा कर न सहने योग्य वर्तमान पर कलई पोत देते हो। हमने स्वीकार कर लिया। हम बदलाव लाएंगे की लहर चली, और रंक राजा हो गए। रंकों का राजा हो जाना बनी बात है भैय्या! आखिर राजा बनने की ठेकेदारी चंद हाथों में क्यों रहे? सपने साकार करने की इजारेदारी ऊंची इमारतों वालों के पास ही क्यों? राजा का बेटा राजा बने, ऐसा तो युगों से देखा था, लेकिन युग बदलने का दम भरने वालों की दुनिया में मजूर का बेटा मजूर ही नहीं, फटीचर बेकार्य हो जाए, ऐसी क्रांति को बतकही होते तो हमने पहली बार देखा आलीजाह! लीजिए हमने जमाना बदल दिया, हमारे नए नुमांइदों ने हमें कहा। नुमांइदे अब भी ऐसे कि जिनमें करोड़पतियों या लखपतियों से नीचे कोई भी नहीं था। उन सब लोगों के दामन पर लगभग कानून तोडने के धब्बे भी थे, लेकिन वे अपराधी नहीं हैं बरखुरदार्य, जानकारों ने हमें बताया। केवल आरोप लगने से ही कोई अपराधी नहीं हो जाता। पहले उनके अपराधी हो जाने का दंडनामा लाइये, फिर हम उनको शासकों की मजलिस से बाहर करेंगे। अब यह दंडनामा कैसे मिलता है, हमें कुछ खबर नहीं। तारीख पर तारीख कानून के दरबार में पेश होते रहो। भाग्य अच्छा रहा तो बेदाग बच निकलोगे। अच्छा न रहा तो कोर्ट से ऊपर की कोर्ट कहीं गई नहीं।

आप का | नजरीया

बढ़ेगा गरीबी का दायरा

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की पश्चिम एशिया युद्ध से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करने वाली रिपोर्ट के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी में ईरान-अमेरिकी युद्ध से उपजी परिस्थितियों के चलते भारत में और 25 लाख लोग गरीबी की दलदल में फंस सकते हैं। साथ ही मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका पैदा हो गई है। रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि से एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट बताती है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से लोगों की घरेलू क्रयशक्ति घट रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ रही है। वहीं विकास कार्यों के लिए निर्धारित सरकारी बजट पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा आजीविका के अवसर कम हो रहे हैं। इस संकट में जहां पूरे विश्व में 88 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने की आशंका है, वहीं भारत में यह अनुमानित संख्या 25 लाख है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एशिया-प्रशांत में तकरीबन 299 अरब डॉलर तक का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, भारत की बड़ी आबादी के सामने बढ़ने वाली गरीबों की संख्या छोटी है, लेकिन इससे भारत में गरीबी की दर बढ़ सकती है, जिसके 35.40 करोड़ होने की आशंका है। दरअसल, आज भी भारत करीब 90 फीसदी तेल जरूरतों के लिए आयात पर आश्रित है। हम कच्चे तेल का 40 फीसदी से अधिक और रसोई गैस का 90 फीसदी आयात पश्चिम एशिया से करते हैं। साथ ही हम अपने उर्वरकों का 40 फीसदी हिस्सा युद्धग्रस्त पश्चिमी एशिया से आयात करते हैं। एलएनजी की कीमतों में वृद्धि से कोयला आधारित बिजली पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर व्यापार व आपूर्ति शृंखला भी प्रभावित हुई। आशंका है कि संघर्ष से रेमिटेंस में भी कमी आएगी। निस्संदेह, मालभाड़ा शुल्क, युद्ध जोखिम बीमा, मार्ग परिवर्तन और देरी की वजह से आयातित तेल आदि की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे आयात मूल्य में वृद्धि व निर्यात का नुकसान बढ़ा है। असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। वहीं खाद की आपूर्ति में बाधा का असर खरीफ की फसल पर पड़ने की आशंका है। इस सब के चलते बढ़े दामों का प्रभाव आम आदमी की जेब पर हो रहा है, जिसका रोजगार और आय के मामले में असर बड़ी आबादी पर नजर आ रहा है। हाल ही में नोएडा और मानेसर में श्रमिक असंतोष को इसकी परिणति के रूप में महसूस किया जा सकता है। दरअसल, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आर्थिक परेशानियों के चलते आम आदमी अब अपने जरूरी खर्चों में कटौती कर रहा है। वजह है उसकी आय के साधन सीमित होना। वहीं निम्न आय वर्ग के लोगों में इससे भरण-पोषण का संकट पैदा हो रहा है। श्रमिक असंतोष के बीच आक्रोश उभरा कि महंगाई के अनुपात में उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, फलतः जीवनयापन कठिन होता जा रहा है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया कि मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.4 हो गई है, जिसकी वजह पश्चिमी एशिया से उपजा संकट बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास सिरे क्यों नहीं चढ़ रहे हैं। यदि कदम प्रभावकारी हैं तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। वास्तव में खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि को महंगाई का मुख्य कारण बताया जा रहा है। यद्यपि सरकार की दलील है कि खुदरा महंगाई दर केंद्रीय बैंक की रेड लाइन चार फीसदी से नीचे है। लेकिन वास्तव में स्थिर आय के चलते महंगाई अधिक महसूस की जा रही है। लेकिन लोगों की चिंता यह है कि यदि पश्चिम एशिया संकट का शीघ्र समाधान नहीं निकलता है तो महंगाई की मार असहनीय हो सकती है। यदि समय रहते सरकार की तरफ से ठोस प्रयास किए जाते हैं तो महंगाई पर अंकुश लगाना संभव हो पायेगा।

ईरान-अमेरिकी युद्ध से उपजी परिस्थितियों के चलते भारत में और 25 लाख लोग गरीबी की दलदल में फंस सकते हैं। साथ ही मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका पैदा हो गई है। रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि से एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट बताती है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से लोगों की घरेलू क्रयशक्ति घट रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ रही है। वहीं विकास कार्यों के लिए निर्धारित सरकारी बजट पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा आजीविका के अवसर कम हो रहे हैं। इस संकट में जहां पूरे विश्व में 88 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने की आशंका है, वहीं भारत में यह अनुमानित संख्या 25 लाख है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एशिया-प्रशांत में तकरीबन 299 अरब डॉलर तक का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, भारत की बड़ी आबादी के सामने बढ़ने वाली गरीबों की संख्या छोटी है, लेकिन इससे भारत में गरीबी की दर बढ़ सकती है, जिसके 35.40 करोड़ होने की आशंका है।

दृष्टि | कोण

पर्यावरण के लिए गंभीर चेतावनी बनता डिजिटल प्रदूषण

जब हम 'प्रदूषण' शब्द सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जहरीला धुआं उगलती चिमनियां, प्लास्टिक से पटी नदियां या सड़कों पर लगा कचरे का ढेर उभरता है। ये प्रदूषण के वे रूप हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इक्कीसवीं सदी की डिजिटल क्रांति के साथ एक ऐसा अदृश्य जहर हमारे वातावरण और जीवन में घुल चुका है, जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन वह धीरे-धीरे हमारे पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है। इसे हम 'डिजिटल प्रदूषण' कहते हैं। भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी चरम पर है और 'डिजिटल इंडिया' का सपना साकार हो रहा है, इस अदृश्य खतरे पर कानून, नीति और जनजागरूकता के नजरिये से चर्चा करना अनिवार्य हो गया है। लोग डिजिटल प्रदूषण को केवल 'ई-वेस्ट' यानी पुराने मोबाइल, टूटे लैपटॉप या खराब चार्जर तक सीमित मान लेते हैं। बेशक, ई-कचरा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'अभौतिक' है। इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशतः जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है। जब हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो हजारों मील दूर स्थित विशाल डेटा सेंटर्स सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें चलाने और ठंडा रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। अतः, डिजिटल गतिविधियों का सीधा और गहरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। डिजिटल प्रदूषण के दो सबसे घातक पहलू 'डार्क डेटा' और 'डिजिटल फुटप्रिंट' हैं। 'डार्क डेटा' वह अनुपयोगी डेटा है जो कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा केवल स्टोर किया जाता है, जिसका दुनिया भर के कॉर्पोरेट डेटा में हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत है। यह डेटा केंद्रों में व्यर्थ ऊर्जा की खपत करता है। वहीं, हमारा 'डिजिटल फुटप्रिंट' भी उतना ही खतरनाक है; एक स्पैम ईमेल अपने पूरे जीवनचक्र में लगभग 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का जिम्मेदार है। यदि

हम दुनियाभर में प्रतिदिन भेजे जाने वाले अरबों स्पैम और अनावश्यक ईमेल की गणना करें, तो यह प्रदूषण का स्तर वैश्विक विमानन उद्योग द्वारा फैलाए जाने वाले कुल उत्सर्जन के बराबर पहुंच जाता है। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी एक छोटी-सी डिजिटल लापरवाही धरती के तापमान को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। भारत में 'डिजिटल प्रदूषण' को सीधे तौर पर परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट या एकल कानून मौजूद नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और समय-समय पर संशोधित ई-कचरा प्रबंधन नियम (2016/2022) इसके केवल भौतिक हिस्से (हार्डवेयर कचरे) को कवर करते हैं। असली चुनौती डेटा केंद्रों से होने वाले ऊर्जा उत्सर्जन और 'डिजिटल हाइजीन' की है, जिसके लिए वर्तमान में स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों की कमी खलती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यद्यपि ये मामले पारंपरिक औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित थे, लेकिन इनमें स्थापित 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा' और 'एहतियाती सिद्धांत' का दर्शन डिजिटल दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। जो कंपनियां विशाल डेटा सेंटर चलाती हैं और करोड़ों भारतीयों का डेटा प्रोसेस करती हैं, वे डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं।'

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर (हिंस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी है। पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाकर प्रदेश में आमजन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवान अथक परिश्रम, अनुशासन और जनसेवा के जज्बे के साथ हर परिस्थिति में ढाल बनकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है तथा हम अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने 77 वर्षों की इस गौरवमयी यात्रा में साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान की अनुपम मिसालें पेश की हैं। शर्मा ने अमर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि शहीदों ने आमजन की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रदेश में सुदृढ़ पुलिसिंग से समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। अच्छी कानून व्यवस्था से राजस्थान की पहचान अब एक शांतिप्रिय राज्य के रूप में बनी है। इससे बड़ी संख्या में निवेशक और पर्यटक प्रदेश में आने के उत्सुक हैं और राज्य अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग से साइबर अपराध, नशा व संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जागरूक नागरिक ही इन अपराधों के खिलाफ सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नवीन कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या के प्रकरणों में 25.68 प्रतिशत, डकैती में 47.26, लूट में 50.75 तथा महिला अत्याचारों में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर एक पुलिस थाना और 17 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। नकल माफिया पर कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, प्रदेश में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और जिससे युवाओं का सरकार में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रभावी कार्य कर रहा है। इससे फायर आर्म्स के उपयोग एवं उनसे होने वाली मौतों में गिरावट आई है। वहीं, साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए सभी पुलिस थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना कर आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस कार्मिकों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक कदम उठाए हैं। प्रदेश के पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 8 हजार से अधिक कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही, प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तथा 23 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 8 पुलिस चौकियों का पुलिस थानों में क्रमोन्नयन, 1 हजार पुलिस मोबाइल यूनिट्स की तैनाती, 35 नवीन पुलिस चौकियां खोलना, कॉन्स्टेबल से सहायक उप निरीक्षक तक के कार्मिकों के स्वीकृत सालाना वर्दी भत्ता में ब ैतरी, पुलिस कर्मियों के मैस भत्ते की राशि में वृद्धि जैसे निर्णयों से पुलिस बल को मजबूत किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिस प्रशिक्षण क्षमता के विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों के निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा पुलिस कार्मिकों के स्पोर्ट्स, वेलफेयर एवं उत्सव फंड में 5 करोड़ रुपए का होगा अतिरिक्त प्रावधान तथा पुलिस कार्मिकों के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 500 आवासों के निर्माण की भी घोषणा की। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है तथा पुलिस द्वारा निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर अपराध पर अंकुश लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में पुलिस बल को आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया करवाए गए हैं। राजस्थान पुलिस कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हुए प्रदेश में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने एवं संविधान मूल्यों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड में आयोजित सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया। इस परेड में राजस्थान पुलिस अकादमी, आरएसी की चौथी व पांचवीं बटालियन, आयुक्तालय जयपुर की निर्भया स्क्वॉड, यातायात कर्मी, हाजी रानी महिला बटालियन अजमेर, एसडीआरएफ, जीआरपी, एमबीसी खैरवाड़ा, ईआरटी और घुड़सवार दल सहित कुल 12 प्लाटून सम्मिलित हुए।

महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने का *नीतीश मॉडल* आज पूरे देश के लिए अनुकरणीय बना : कुशवाहा

पटना (हिंस)। बिहार जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसका परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं मेयर, जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड पार्षद जैसे पदों तक पहुंचकर जनसेवा की मिसाल कायम कर रही हैं। कुशवाहा ने एक बयान में कहा कि महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से नीतीश कुमार द्वारा प्रस्तुत महिला सशक्तिकरण का मॉडल और उनके द्वारा दिखाई गई राह आज पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि यह पूरे देश, विशेषकर आधी आबादी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि संसद के इस ऐतिहासिक विशेष सत्र के माध्यम से केंद्र की एनडीए सरकार *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* के तहत लोकसभा एवं देशभर की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने जा रही है। यह देश की लोकतांत्रिक संरचना को अधिक समावेशी, संतुलित और सशक्त बनाने की दिशा में एक दूरगामी एवं परिवर्तनकारी कदम है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक महिलाओं को उनको उचित और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक विकसित भारत का संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता। इस सत्य को हमारे नेता नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही आत्मसात कर लिया था। यही कारण है कि उन्होंने सत्ता की बागडोर संभालते ही महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण-केंद्रित नीतियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। परिणामस्वरूप आज समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने तख्त श्रीहरिमंदिर जी में मत्था टेका राज्य के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की

पटना (हिंस)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्रीहरिमंदिर जी परिसर, पटना साहिब पहुंचे। मुख्यमंत्री ने तख्त श्रीहरिमंदिर जी, पटना साहिब में मत्था टेका और राज्य के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक कमिटी के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री को तलवार, अंगवस्त्र, सरोपा एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गुरु की प्रेरणा से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। नीतीश कुमार ने बिहार का लंबे समय तक नेतृत्व करते हुए राज्य को आगे बढ़ाया है। हमलोगों ने बेहतर तरीके से 350वां प्रकाश पर्व मनाया है। यहां की संरचना को काफी बेहतर किया गया है। श्री गुरुगोविंद सिंह जी महाराज की पूरे प्रदेश पर कृपा बनी रहे। राज्य समृद्ध हो, देश विकसित हो, यही हमारी कामना है। इस अवसर पर विधायक डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेन्द्र राणा, पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी के सदस्यगण, सेवादार एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे।

नमी मानकों में ढील न मिलने से किसान परेशान, सीएम मान जिम्मेदार : सुखबीर

खन्ना अनाज मंडी दौरे में सरकार पर बरसे अकाली दल अध्यक्ष, खरीद व्यवस्था पर उठाए सवाल

खन्ना (हिंस)। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गेहूं की नमी के मानकों में ढील न दिलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस कारण किसानों की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है और वे भारी परेशानी झेल रहे हैं। खन्ना की एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक का दौरा करते हुए बादल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब सरकार समय रहते केंद्र से नमी मानकों में छूट नहीं ले पाई, जबकि हरियाणा और राजस्थान ने पहले ही यह राहत हासिल कर ली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने देरी से आवेदन किया, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जब उन्हें मंडियों का दौरा कर खरीद प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए, तब वे छुट्टियों और विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। अकाली दल अध्यक्ष ने कहा कि किसान पहले ही बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान झेल चुके हैं और अब अधिक नमी के कारण खरीद एजेंसियां गेहूं नहीं खरीद रहीं।

उन्होंने एक किसान का हवाला देते हुए दावा किया कि मंडियों में केवल 2-3 प्रतिशत फसल ही खरीदी जा रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर बोरों की कमी और घटिया गुणवत्ता के बोरे उपलब्ध कराने का भी आरोप लगाया। बादल ने पार्टी नेताओं से सभी मंडियों का दौरा कर किसानों के हक में आवाज उठाने की अपील की। परिसीमन पर उन्होंने कहा कि इसे केवल जनसंख्या के आधार पर लागू करना उचित नहीं है और सभी राज्यों के साथ समानता बरती जानी चाहिए।

चुनावी प्रक्रिया में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर रोक

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने चुनावों के मद्देनजर गुरुवार को नगर निगम पंचकूला एवं अंबाला के अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश जारी किए। देवेंद्र सिंह कल्याण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची, ईवीएम, चुनाव सामग्री, कानून व्यवस्था, संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान, मतदान कर्मियों की तैनाती, प्रशिक्षण, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं तथा दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं सहित सभी प्रबंध समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाएं। देवेंद्र सिंह कल्याण ने कहा कि 13 अप्रैल 2026 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक नहीं किया जाएगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार की नई योजना- परियोजना का शिलान्यास व उद्घाटन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि नगर निगम पंचकूला की वार्डवार अंतिम मतदाता सूची 27 मार्च 2026 को प्रकाशित की जा चुकी है। नियमों के अनुसार चुनाव कार्यक्रम जारी होने से नामांकन की अंतिम तिथि तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने का अधिकार रहेगा। केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम संबंधित वार्ड में जोड़े जा सकेंगे, जिनका नाम विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मौजूद है, लेकिन नगर निगम की वार्डवार सूची में शामिल नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी संभावित प्रत्याशी का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में विधिवत शामिल है तो उसे नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की तुरंत पहचान कर वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। देवेंद्र कल्याण ने कहा कि मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध रहे। बैठक में 09 मई से 13 मई 2026 तक बिजली और पेयजल आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने पर बल दिया गया। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने, स्पष्ट संकेतक लगाने तथा एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एवं गाइड्स के स्वयंसेवकों की सहायता लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि वोटर स्लिप 7 मई तक प्रत्येक घर तक पहुंचाकर वितरित की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्लिप्स थोक में न दी जाएं, बल्कि घर-घर जाकर व्यवस्थित रूप से वितरण किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

हरियाणा में ऑनलाइन जनगणना शुरू, मुख्यमंत्री ने की शुरुआत

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर कर राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से उन्होंने प्रदेशवासियों को जनगणना में सक्रिय भागीदारी करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि स्व-गणना की प्रक्रिया बेहद सरल और समय की बचत करने वाली प्रणाली है। जनगणना-2027 विकसित हरियाणा-विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है और यह केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि राज्य के समग्र और न्यायसंगत विकास की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जनगणना का प्रथम चरण 1 मई से 30 मई, 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें मकानों की गणना एवं सूचीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इससे पूर्व 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नागरिकों को डिजिटली स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो

डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सटीक और विश्वसनीय जनगणना आंकड़े ही ऐसी नीतियों और योजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित करते हैं, जो समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि भारत में जनगणना का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी व्यवस्थित शुरुआत वर्ष 1872 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यह देश की 8वीं और हरियाणा के गठन के बाद 6वीं जनगणना है। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिससे यह अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनेगी। स्व-गणना सुविधा के तहत नागरिक अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल विकसित किया गया है, जहां नागरिक मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी आधारित लॉगिन कर अपने राज्य, जिला और स्थानीय विवरण का चयन कर डिजिटल मानचित्र पर अपने घर को चिह्नित करेंगे और परिवार एवं आवास से संबंधित जानकारी दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और गोपनीय बताया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त और जनगणना के लिए हरियाणा स्टेट नोडल ऑफिसर डॉ सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में 2011 के बाद जनगणना हो रही है। इस बार की जनगणना की खास बात यह है कि इस बार डिजिटल रूप से जनगणना की जा रही है। 16 से 30 अप्रैल तक नागरिक पोर्टल पर जाकर स्व-गणना कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनगणना के लिए लगभग 60 हजार कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, जनगणना करने वाले कर्मियों के लिए मानदेय भी बढ़ाया है। निदेशक, जनगणना श्री ललित जैन ने कहा कि आज हरियाणा के 51000 एन्यूमरेशन ब्लॉक्स को डिजिटलाइज कर दिया है और इनका सारा नजीर नक्शा पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे राज्य के नागरिक आसानी से स्व गणना कर सकेंगे। यह सारा डेटाबेस हरियाणा के विकास के लिए सहायक होगा।

समाजवादी पार्टी पर जिन्ना की सोच हावी हो चुकी : आनंद दुबे

लखनऊ (हिंस)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए देश में अलग से सीटें आरक्षित करने की मांग करने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने गुरुवार को कहा कि समाजवादी पार्टी पर जिन्ना की सोच हावी हो चुकी है। उन्होंने कहा सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण इस तरह हावी हो गया कि हर जगह उन्हें सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देता है। जिस तरह से जिन्ना मुसलमानों के लिए देश में अलग से आरक्षित चुनाव क्षेत्र की मांग करते थे, आज उसी तरह महिला आरक्षण पर बात करते हुए संसद में सपा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए देश में अलग से सीटें आरक्षित करने की मांग की। यह वही जिन्ना वाली सोच है जिसने देश का बंटवारा कराया। संविधान और बाबा साहेब का नाम लेने वाली समाजवादी पार्टी की असलियत यही है। विदित हो कि गुरुवार को सपा के सदस्यों ने संसद में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की मांग की।

पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या, चार बच्चों का छिना सहारा

चंडीगढ़ (हिंस)। अमृतसर जिले के गांव भुल्लर में पुरानी रंजिश के चलते बीती देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर गांव के आसपास के ही रहने वाले हैं और उनका संबंध गैंगस्टर गतिविधियों से बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मनजीत सिंह अपनी चिकन शॉप के बाहर कार में बैठे हुए थे। इसी दौरान हमलावर अचानक मौके पर पहुंचे और बिना किसी बातचीत के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल मनजीत सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिवारिक सदस्य मलकीत सिंह ने बताया कि यह मामला पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में भी आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद रंजिश खत्म नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की, जिनमें से 3 गोलियां मनजीत सिंह को लगीं।

जनमित्र की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है पुलिस : सांगवान

धौलपुर (हिंस)। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का आयोजन गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाईन धौलपुर में किया गया। इस अवसर पर सरेमोनियल परेड हुई तथा पुलिस कर्मियों को सेवा चिन्हों से सम्मानित किया गया। आयोजन में जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि वर्दी अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। पुलिस के जवानों ने नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए अनेक अवसरों पर त्याग एवं बलिदान के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पुलिस की कार्य प्रणाली में निरंतर सुधार लाने के साथ ही आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य कर पुलिस और निरंतर जनमित्र की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपने ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर को ध्यान में रखकर सदैव नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर रहें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा द्वारा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू होकर समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। आज ही आरएसी लाईन में लाइन में वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ मुख्यालय बाडी कमल कुमार जांगिड सहित समस्त वृत्ताधिकारीगण और थानाधिकारी गण, सीएलजी सदस्य एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

कांस्टेबल की सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बची

बाड़मेर (हिंस)। जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब बेकाबू हुई रोडवेज बस को एक कांस्टेबल ने अपनी सूझबूझ से नियंत्रित कर लगभग 35-40 यात्रियों की जान बचा ली। यह घटना बलाऊ फांटे के पास की है। जानकारी के अनुसार, बाड़मेर से चौहटन जा रही रोडवेज बस के आगे चल रही एक पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इस दौरान बस चालक संतुलन खो बैठा और ब्रेक लगाने के प्रयास में सीट से नीचे गिर गया, जिससे बस बेकाबू हो गई। बस के केबिन में बैठे धनाऊ थाने के कांस्टेबल जेठाराम ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए स्टेयरिंग संभाल लिया। उन्होंने बताया कि अचानक ड्राइवर के गिरने से कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने तुरंत ड्राइवर की सीट संभालकर बस को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि बस के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, ऐसे में कांस्टेबल ने जोखिम उठाते हुए बस को सड़क से नीचे उतार दिया, ताकि उसे किसी तरह रोका जा सके।

महिलाओं के प्रति सम्मान की संस्कृति को मजबूत करने का माध्यम है नारी शक्ति वंदन : सुषमा पटेल

जौनपुर (हिंस)। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से नारी शक्ति वंदन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गुरुवार को एक विशाल पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने भारी संख्या में भाग लिया, जो महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के संकल्प को दर्शाता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुषमा पटेल ने नारी शक्ति वंदन पर अपना बयान देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन न केवल एक अभियान है, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की संस्कृति को मजबूत करने का माध्यम है। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि नारी शक्ति का वंदन हर घर, हर गली में गूंजे। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र की सरकार ने महिलाओं के हितों के लिए यह कदम उठाया है, जो कि सराहनीय कदम है। कुलसचिव केश लाल ने कहा कि विश्वविद्यालय इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध है। नारी शक्ति वंदन जैसे प्रयास विद्यार्थियों में नैतिकता और सम्मान की भावना विकसित करेंगे। यह विद्यार्थियों को दायित्व के साथ -साथ कर्तव्यबोध

भी कराता है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद सिंह ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज-सेवी भी बनाना है। यह पदयात्रा छात्रों को नारी सम्मान के प्रति जागरूक करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों ने 9667173333 नंबर पर मिस्ड काल कर भारत सरकार की वेबसाइट पर नारी शक्ति वंदन के पक्ष में अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम संयोजक डॉ. जाह्नवी श्रीवास्तव ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत यह पदयात्रा मुख्य द्वार से होते हुए परिसर में भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस संदेश को हर स्तर तक पहुंचाया जाए। इस अवसर पर कुलपति प्रो. अविनाश पाथर्डीकर, प्रो. प्रमोद यादव, प्रो. मनोज मिश्र, प्रो. गिरधर मिश्र, डॉ. मनोज पांडेय, डॉ.सुनील कुमार, डॉ. मंगला यादव, उपकुलसचिव बबिता सिंह, डॉ.अनु त्यागी, डॉ. वनिता सिंह, डॉ. प्रियंका, डॉ. सोनम झा, सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

परशुराम जयंती महोत्सव आज से

जोधपुर (हिंस)। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती के पावन अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा जोधपुर इकाई के तत्वावधान में परशुराम महादेव मंदिर में तीन दिवसीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न होगा, जिसमें पूजा-अर्चना, संत समागम, भजन संध्या एवं सम्मान समारोह सहित अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष डॉ. आनंदराज पुरोहित ने बताया कि यह आयोजन भोगीशैल पर्वतमाला स्थित सिवांची गेट स्वर्गाश्रम के आगे परशुराम महादेव मंदिर परिसर में होगा। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को सुबह गणपति पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसके बाद संत समागम आयोजित किया जाएगा। अगले दिन 18 अप्रैल को भगवान परशुराम के विग्रह का विशेष अभिषेक किया जाएगा। इस दौरान इत्र, पंचामृत, शहद, केसर एवं 101 किलो दूध से अभिषेक होगा। साथ ही 51 वेदपाठियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अंतिम दिन 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी तथा सायं 6 बजे सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 16वां परशुराम पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। साथ ही दो विशिष्ट व्यक्तियों को

लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीत पुरोहित मुख्य अतिथि होंगे। वहीं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाजसेवी नगेंद्र शर्मा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सत्यप्रकाश बोहरा ने बताया कि इस अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। तीनों दिनों तक मंदिर में पूजा-पाठ, धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। इस आयोजन में पीपीएस सोसायटी एवं पुष्टिकर महिला महाविद्यालय, सिवांची गेट का विशेष सहयोग रहेगा।

पश्चिमी एशिया संकट के बावजूद एलपीजी की मारामारी खत्म, सिलेंडर बुकिंग में कमी

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की बुकिंग के लिए मची मारामारी अब काफी हद तक खत्म हो गई है। एक महीने पहले जहां दैनिक बुकिंग 90 लाख तक पहुंच गई थी, वहीं अब यह घटकर 43 लाख रह गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और सरकार के त्वरित कदमों के कारण स्थिति सामान्य हो रही है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 14 अप्रैल को सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने

सरकारी प्रयासों और वैकल्पिक आपूर्ति से स्थिति सामान्य हुई, मांग-आपूर्ति का अंतर पाटा गया

घरेलू उपभोक्ताओं को 43.1 लाख सिलिंडरों की बुकिंग के मुकाबले 47.6 लाख एलपीजी सिलिंडर वितरित किए, जो आपूर्ति व्यवस्था के दुरुस्त होने का संकेत है। पश्चिम एशिया संकट से पहले घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की औसत दैनिक मांग लगभग 55 लाख थी, और अब आपूर्ति तथा मांग के अंतर को काफी हद तक पाट लिया गया है।

रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन में वृद्धि, सिलिंडर बुकिंग के बीच लंबे अंतराल, विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति को प्राथमिकता देने और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने जैसे कदमों से स्थिति को संभालने में खासी मदद मिली है। भारत ने पश्चिम एशिया से बाधित आपूर्ति की भरपाई के लिए अमेरिका, अंगोला और ईरान सहित अन्य देशों से एलपीजी की खरीद बढ़ाई है। केंद्र सरकार ने भी स्थिति पर बारीकी से नजर रखी है। सरकार के अनुसार, अब किसी भी वितरक कंपनी के पास ड्राई-आउट जैसी स्थिति नहीं है और आनलाइन बुकिंग 84 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गई है।

आटो एलपीजी की बिक्री में भी अप्रैल में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और खाद्य जैसे अहम क्षेत्रों के लिए सी3 और सी4 गैसों की मात्रा को पहले के 800 टन/दिन से बढ़ाकर 1,000 टन प्रतिदिन कर दिया है। सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन के लिए इन गैसों का पूरा उपयोग करने का निर्देश दिया था।

न्यूज ब्रीफ

क्वालकाम और बाश मिलकर अडास साल्युशन करेंगी विकसित

नई दिल्ली। क्वालकाम और बाश कंपनी ने अडास (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) टेक्नोलाजी को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए हाथ मिलाया है। अपने डिजिटल काकपिट कंप्यूटरों की सफलता के बाद, ये दोनों कंपनियां मिलकर वाहन निर्माताओं के लिए अडास साल्युशन विकसित करेंगी। इस साझेदारी के तहत, बाश क्वालकाम के स्नैपड्रैगन राइड हार्डवेयर पर आधारित इन-कार कंप्यूटर तैयार करेगा। ये कंप्यूटर अडास की विभिन्न सुविधाओं को आपरेट करेंगे। कार निर्माता एक ही स्नैपड्रैगन राइड प्लैक्स एसओसी पर आधारित काकपिट और अडास हार्डवेयर साल्युशन का चयन कर अपनी लागत को कम कर सकते हैं, जिससे उन्हें साफ्टवेयर-डिफाइंड वाहनों के विकास में मदद मिलेगी। कंपनियों का कहना है कि यह स्केलेबल और माड्यूलर प्लेटफार्म हाई बैंडविड्थ और कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करेगा, जिससे तेज गति से चलती कार में भी सटीक एनवायरमेंट माडलिंग संभव होगी और ड्राइवर-यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह समाधान शुरुआती स्तर के अडास वर्किंग (जैसे स्पीड/डिस्टेंस कंट्रोल) से लेकर एडवांस्ड आटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम तक का समर्थन करेगा।

ओप्पो पेड 5 प्रो अपनी बड़ी बैटरी के कारण सुर्खियों में

नई दिल्ली। चाइनीज कंपनी ओप्पो का नया फ्लैगशिप टैबलेट, ओप्पो पेड 5 प्रो, अपनी बड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले के कारण लाचिंग से पहले ही सुर्खियों में है। यह तेजतर्रार टैबलेट 21 अप्रैल को चीन में आधिकारिक तौर पर लान्च किया जाएगा। आगामी ओप्पो पेड 5 प्रो में 13.2 इंच का बड़ा डिस्प्ले होगा, जिसका रिजाल्यूशन 1920गुणा1200 पिक्सेल और आस्पेक्ट रेशियो 16:9 होगा। परफार्मेंस के लिए इसमें क्वालकाम का पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 (एसएम8850पी) चिपसेट लगा होगा, जो इसे फ्लैगशिप कैटेगरी में लाता है। यह एंड्राएड पर चलेगा और गेमिंग, वीडियो एडिटिंग व मल्टीटास्किंग के लिए जबरदस्त परफार्मेंस देगा। फोटोग्राफी के लिए, इसमें 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा मिलने की उम्मीद है, जबकि कुछ लीक्स 8 मेगापिक्सेल के फ्रंट कैमरे का भी संकेत देते हैं, जो डाक्यूमेंट स्कैनिंग और कभी-कभार की फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त होगा। यह एक वाईफाई-ओनली डिवाइस होगा, जो सेल्युलर कनेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेगा। यह टैबलेट 8जीबी प्लस 256जीबी, 12जीबी प्लस 256जीबी, 12जीबी प्लस 512जीबी और 16जीबी प्लस 512जीबी जैसे कई कान्फिगरेशन में उपलब्ध होगा।

कम मेंटेनेंस वाली 5 बाइक्स खूब आ रही ग्राहकों को पसंद

नई दिल्ली। दो पहिया वाहनों के बाजार में इन दिनों कम मेंटेनेंस वाली 5 बाइक्स मौजूद है जो ग्राहकों द्वारा बेहद प्रसंद की जा रही है। आजकल बाजार में दैनिक उपयोग, विश्वसनीयता व कम मेंटेनेंस के लिए 5 बेहतरीन बाइक्स मौजूद है इनमें यामाहा एमटी-15 वी2 प्रमुख है। स्टाइल और पावर चाहने वालों के लिए यह 155सीसी इंजन वाली बाइक एकदम सही है। इसका रिफाइंड इंजन, शहर के ट्रैफिक में आसान हैंडलिंग और हाई-परफार्मेंस के बावजूद भरोसेमंद होना इसे खास बनाता है। इसी तरह टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी अपनी कैटेगरी में सबसे स्मूथ मानी जाने वाली यह बाइक विभिन्न राइडिंग मोड्स के साथ आती है। इसकी मजबूत बनावट और इंजन क्वालिटी इसे रोजाना 40-50 किलोमीटर चलाने के लिए आदर्श बनाती है। स्पोर्टी लुक और कम मेंटेनेंस चाहने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। वहीं भारतीय सड़कों पर भरोसे का पर्याय, स्प्लेंडर प्लस अपनी बेजोड़ मजबूती और टिकाऊपन के लिए हीरो स्प्लेंडर प्लस जानी जाती है। समय पर सर्विस से यह सालों-साल बिना शिकायत चलती रहती है, जो इसे बचत और भरोसे के मामले में शीर्ष पर रखती है।

युद्ध की छाया में वैश्विक रक्षा व्यय रिकार्ड स्तर पर, आईएमएफ ने आर्थिक असंतुलन पर चेताया

रिपोर्ट में भारत के लिए भी अहम संदेश; राजकोषीय असंतुलन और सामाजिक खर्च में कटौती का बढ़ा खतरा

नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी अप्रैल की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में वैश्विक रक्षा खर्च में चिंताजनक वृद्धि को उजागर किया है। रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा भू-राजनीतिक संघर्षों, जिनमें अमेरिका और इजरायल का ईरान के साथ जारी तनाव भी शामिल है, के कारण रक्षा व्यय शीत युद्ध (1991 में समाप्त) के बाद के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। आईएमएफ ने सरकारों को इस बढ़ती प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाले संभावित आर्थिक असंतुलन के प्रति आगाह किया है, जिसमें सार्वजनिक ऋण में वृद्धि और सामाजिक खर्च में कटौती का खतरा प्रमुख है। यह रिपोर्ट भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत का रक्षा बजट उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2 फीसदी से कम है फिर भी वह रक्षा आयात और खर्च के मामले में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल है। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत की प्रति व्यक्ति आय काफी कम है, और उसे अपनी अनूठी सामाजिक वास्तविकताओं के साथ-साथ पड़ोसियों के साथ कई अहम रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आईएमएफ चेतावनी देता है कि दशकों की गिरावट के बाद रक्षा खर्च में अचानक उछाल अक्सर राजकोषीय और बाहरी संतुलन को कमजोर करता है।

रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के दौरान खर्च बढ़ने से सार्वजनिक ऋण में भारी वृद्धि होती है और सामाजिक मदों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य) पर व्यय में कमी आती है। इसके विपरीत, शांति काल में आर्थिक तेजी से उत्पादन बढ़ता है बिना कर्ज बढ़ाए या सामाजिक खर्च घटाए। बढ़ी हुई मांग और कुछ हद तक विदेशी सैन्य उपकरणों की खरीद चालू खाते की स्थिति को बिगाड़ सकती है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि मौजूदा रक्षा विस्तार का व्यापक आर्थिक प्रभाव पहले से अलग हो सकता है, क्योंकि व्यय अब अधिक पूंजी लागत और अनुसंधान पर केंद्रित है, खासकर अत्यधिक एकीकृत और ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं में। आईएमएफ नीति निर्माताओं से आग्रह करता है कि वे रक्षा तैयारियों को विश्वसनीय मध्यावधि राजकोषीय ढांचे के तहत एकीकृत करें। उन्हें उच्च लागत बोझ से निपटने के लिए व्यापक आर्थिक स्थितियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना चाहिए और निर्माण की गति को सुचारू बनाना चाहिए ताकि संसाधनों के पुनर्वितरण में बाधाओं को कम किया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध (1945) के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि सरकारों ने अक्सर उधारी के माध्यम से खर्च में वृद्धि की है, और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण प्रबंधन आवश्यक है।

चीन की अर्थव्यवस्था में रफ्तार, लेकिन मांग की कमजोरी बनी चुनौती

नई दिल्ली। साल 2026 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। हालांकि सतह पर दिख रही मजबूती के पीछे मांग की कमजोरी एक बड़ी चिंता के रूप में उभर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था ने 2026 की पहली तिमाही में रफ्तार पकड़ी है। तिमाही आधार पर देश की जीडीपी में 1.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछली तिमाही के 1.2 फीसदी से अधिक है। यह बढ़त 2024 के अंत के बाद सबसे मजबूत मानी जा रही है, जिससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। इस सुधार के पीछे सरकार की ओर से दिया गया लगातार समर्थन अहम भूमिका निभा रहा है। नीतिगत प्रोत्साहन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों ने ग्रोथ को सहारा दिया है। हालांकि, तस्वीर पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि उत्पादन में तेजी के बावजूद बाजार में मांग उतनी मजबूत नहीं है। फैक्ट्रियां तेजी से उत्पादन कर रही हैं, लेकिन उपभोक्ता मांग कमजोर बनी हुई है। यह असंतुलन चीन की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। व्यापार तनाव, अनिश्चित आर्थिक माहौल और कमजोर वैश्विक मांग का असर चीन पर पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में आगे की राह कठिन हो सकती है। इस सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार ने बजट घाटा बढ़ाकर जीडीपी के करीब 4 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।

यात्री वाहन निर्यात में मारुति और हुंडई का दबदबा, 70 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी

नई दिल्ली

भारत से यात्री वाहनों के निर्यात में वित्त वर्ष 26 में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 9,05,200 वाहनों के निर्यात के साथ देश के आटोमोबाइल सेक्टर ने अपनी वैश्विक पहुंच को मजबूत किया है। इस उछाल की अगुवाई प्रमुख वैश्विक कार विनिर्माताओं, मारुति सुजूकी इंडिया और हुंडै मोटर इंडिया ने की, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी 70.03 प्रतिशत रही। सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के आंकड़ों के अनुसार, मारुति और हुंडै की यह हिस्सेदारी वित्त वर्ष 25 के 64.05 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है। यदि तीसरी सबसे बड़ी निर्यातक निसान इंडिया को भी शामिल किया जाए, तो इन तीनों कंपनियों की संयुक्त हिस्सेदारी 80 प्रतिशत तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 25 में यह आंकड़ा 73 प्रतिशत था। इस वृद्धि की मुख्य चालक मारुति सुजूकी इंडिया रही, जिसने वित्त वर्ष 26 में 34.4 प्रतिशत की भारी वृद्धि के साथ 4,43,825 वाहनों का रिकार्ड निर्यात किया। वहीं, हुंडै इंडिया का निर्यात

यात्री वाहनों के निर्यात में वित्त वर्ष 26 में कुल निर्यात 9 लाख के पार

16.36 प्रतिशत बढ़कर 1,90,725 इकाई और निसान इंडिया का निर्यात 15.5 प्रतिशत बढ़कर 84,408 इकाई हो गया। नतीजतन, समूचे यात्री वाहन निर्यात में वित्त वर्ष 26 में सालाना आधार पर लगभग 15 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। इसके विपरीत, अग्रणी घरेलू यात्री वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से काफी पीछे रह गए। वित्त वर्ष 26 में यात्री वाहनों के कुल निर्यात में उनकी संयुक्त हिस्सेदारी मात्र 3.2 प्रतिशत (29,072 वाहन) रही, जो किआ मोटर्स इंडिया के निर्यात से कुछ ही अधिक थी। यह स्थिति विचारणीय है, खासकर तब जब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना चला रही है।

महिंद्रा की एसयूवी गाड़ियों ने बिक्री के नए रिकार्ड बनाए

नई दिल्ली। फाइनेंशियल ईयर (एफवाय2026) महिंद्रा के लिए किसी लाटरी से कम नहीं रहा, जब कंपनी की एसयूवी गाड़ियों ने बिक्री के नए रिकार्ड बनाए। महिंद्रा कंपनी ने स्कार्पियो, थार और बोलेरो की तिकड़ी ने मिलकर 4 लाख से अधिक गाड़ियां बेच डालीं। पूरे साल में महिंद्रा ने कुल 6,60,276 वाहन बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा है। इस जबरदस्त प्रदर्शन के साथ महिंद्रा भारत में दूसरी सबसे बड़ी वाहन विक्रेता कंपनी बन गई है। महिंद्रा स्कार्पियो (एन और क्लासिक) की बिक्री 1,79,000 यूनिट्स तक पहुंची, जिसमें सालाना आधार पर 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, महिंद्रा थार की लोकप्रियता में भारी उछाल आया और इसकी बिक्री में करीब 49 प्रतिशत की तगड़ी बढ़ोतरी हुई, कुल 1,26,261 यूनिट्स बिकीं। शहर से लेकर पहाड़ों तक, थार और स्कार्पियो का जलवा कायम रहा। दो दशक से अधिक पुरानी महिंद्रा बोलेरो ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

सर्राफा बाजार में तेजी से महंगा हुआ सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोना 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,420 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी शुरुआती कारोबार के दौरान 11,800 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी फिजिकल गोल्ड 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,820.45 डालर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया है। इसी तरह चांदी भी 78.61 डालर प्रति औंस की कीमत पर बिक रहा है।

घरेलू सर्राफा बाजार में कीमत में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,55,360 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,56,230 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,42,410 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,43,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। इसी तरह चांदी के भाव में आई तेजी के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,70,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,55,510 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,560 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,55,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,410 रुपये

प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,55,410 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,56,230 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,43,300 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,55,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,42,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,410 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,42,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ग्लोबल मार्केट से पाजिटिव संकेत, एशिया में भी चौतरफा तेजी का रुख

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में शांति समझौता होने की बढ़ती उम्मीद के बीच ग्लोबल मार्केट से पाजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जान्स फ्यूचर्स भी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। वहीं एशियाई बाजार में खरीदारी का रुख बना हुआ है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में युद्ध खत्म होने के बहुत करीब है, कह कर पिछले सत्र के दौरान वाल स्ट्रीट में जोश का माहौल बना दिया। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.80 प्रतिशत की मजबूती के साथ 7,022.95 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 376.93 अंक यानी 1.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,016.02 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.10 प्रतिशत की बढ़त के

साथ 48,514.27 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 10,559.58 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.64 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,274.57 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,066.70 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल बना हुआ है। एशिया के सभी प्रमुख नौ बाजार के सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 143 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,392.50 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह ताइवान वेटेड इंडेक्स 251.39 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ 36,973.53 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

निक्केई इंडेक्स ने जोरदार छलांग लगाई है। फिलहाल यह सूचकांक 1,320.76 अंक यानी 2.27 प्रतिशत उछल कर 59,455 अंक के स्तर पर आ गया है। इसी तरह कोस्पी इंडेक्स 115.82 अंक यानी 1.90 प्रतिशत की मजबूती के साथ 6,207.21 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। हैंग सेंग इंडेक्स में भी जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 414.68 अंक यानी 1.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,362 अंक के स्तर पर आ गया है। इसके अलावा शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.53 प्रतिशत की छलांग लगा कर 4,048.64 अंक के स्तर पर, जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.18 प्रतिशत उछल कर 7,637.07 अंक के स्तर पर, सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की मजबूती के साथ 1,507.67 अंक के स्तर पर और स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 5,023.22 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

आईपीएल में वापसी के लिए तैयार पैट कमिंस, गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट

नई दिल्ली

आस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सिडनी में कराए गए ताजा स्कैन के बाद बिना किसी प्रतिबंध के गेंदबाजी करने की अनुमति मिल गई है, जिससे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो गया है।

बुधवार को हुए स्कैन में यह पुष्टि हुई कि उनकी पीठ की स्ट्रेस इंजरी, जिसने पिछले साल अगस्त के बाद उन्हें सिर्फ एक पेशेवर मैच खेलने तक सीमित कर दिया था, अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है।

आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज अब शुक्रवार को भारत लौटेंगे और आईपीएल के बाकी मैचों के लिए सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ेंगे, जहां वह अपने आस्ट्रेलियाई साथी ट्रैविस हेड के साथ खेलेंगे।

हालांकि सनराइजर्स इस सत्ताहांत चेन्नई सुपर किंग्स और अगले बुधवार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ घरेलू मुकाबले खेलेगी, लेकिन कमिंस जल्दबाजी में वापसी नहीं करना चाहते। वह 25 अप्रैल को जयपुर में राजस्थान रायल्स के खिलाफ मैच में प्लेइंग इलेवन में लौटने का लक्ष्य बना रहे हैं।

कमिंस के टीम में लौटते ही कसानी भी उनके हाथों में वापस आने की संभावना है। उनकी अनुपस्थिति में टीम की कमान ईशान किशन संभाल रहे थे। फिलहाल टीम दो जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है।

कमिंस की वापसी उनकी योजना के अनुसार है, जिसमें वह टूर्नामेंट के दूसरे चरण और संभावित प्लेआफ मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहते थे। इसके बाद आस्ट्रेलिया के लिए एक व्यस्त टेस्ट क्रिकेट कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें अगले 12 महीनों में लगभग 21 टेस्ट मैच खेले जा सकते हैं।

हाल ही में कमिंस ने तीनों फार्मेट में खेलने की अपनी इच्छा दोहराई है। उन्होंने कहा कि वह टेस्ट और वनडे कप्तान के रूप में महत्वपूर्ण सीरीज को प्राथमिकता देंगे और खुद को फिट रखने के लिए दो से तीन महीने का ब्रेक भी लेते रहेंगे। उन्होंने बिजनेस आफ स्पोर्ट पाडकास्ट में कहा, मैं अभी भी तीनों फार्मेट खेलना चाहता हूं और मुझे लगता है कि हम इसे संतुलित कर सकते हैं। मुझे टेस्ट क्रिकेट बेहद पसंद है। उम्मीद है कि अगले 3-5 साल तक मैं इसी तरह खेलता रहूं और टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना न पड़े। आस्ट्रेलिया का टेस्ट कार्यक्रम अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की सीरीज से शुरू होगा, जो डार्विन और मैके में खेली जाएगी। इसके बाद टीम दक्षिण अफ्रीका में तीन टेस्ट, घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट, फिर अगले साल जनवरी-फरवरी में भारत दौरे पर पांच टेस्ट खेलेगी। मार्च में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 150वीं वर्षगांठ टेस्ट और जून में लार्ड्स में संभावित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी शामिल है, इसके बाद एशेज सीरीज के पांच टेस्ट मैच होंगे। करीब 4 मिलियन आस्ट्रेलियाई डालर के अपने आईपीएल कान्ट्रैक्ट को पूरा करना भी कमिंस के कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। टीम के कोच डेनियल विटोरी ने उनकी फिटनेस को शानदार बताया है। विटोरी ने कहा, उनकी फिटनेस बेहतरीन रही है क्योंकि वह लंबे समय से मैदान से बाहर थे और इस दौरान उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर काफी काम किया। गेंदबाजी के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करना एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया होती है।

न्यूज ब्रीफ

आयुष म्हात्रे के खेल से प्रभावित हैं ब्रेविस

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने टीम के उभरते हुए बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उसका खेल लाजवाब है। ब्रेविस के अनुसार जिस प्रकार से आयुष निडर होकर बल्लेबाजी करते है उसका कोई जवाब नहीं है। साथ ही कहा कि इस बल्लेबाज को खेलते देखने उन्हें काफी अच्छा लगता है। रविचंद्रन अश्विन और डेल स्टेन के साथ बातचीत के दौरान, ब्रेविस ने आयुष के धमाकेदार प्रदर्शन को लेकर ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि म्हात्रे एक अलग तरह के बल्लेबाज हैं। साथ ही कहा कि वह युवा हैं और जिस तरह से चाहते हैं खेलते हैं। मेरा भी यही मानना है कि वह अपने अनुसार खेलें। साथ ही कहा कि आपके करियर में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं पर ये देखना शानदार है कि वह कैसे खेलते हैं। ब्रेविस की इस बात से साफ है कि आयुष के खेले से उनकी टीम के साथी किस प्रकार से प्रभावित हैं। इसके अलावा, ब्रेविस ने कोलकाता के खिलाफ अपने स्वयं के प्रदर्शन और टीम की जीत पर भी खुशी जतायी। उन्होंने मैच के अनुभव को बेहतरीन बताया और कहा कि चेन्नई में दर्शकों की उत्साही भीड़ के सामने खेलना खास अनुभव रहा। ब्रेविस ने पिच की स्थिति पर भी बात की, यह स्वीकार करते हुए कि विकेट को समझने में कुछ समय लगा, क्योंकि यह पिछली रात की तुलना में थोड़ा अलग था। ब्रेविस ने कहा, मैदान पर डाइव लगाना, बल्ले से अच्छा स्विंग करना और बस उसे महसूस करना बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी फिटनेस और आत्मविश्वास को लेकर भी बताया और कहा कि मेरा मनोबल भी बढ़ गया है क्योंकि साइड स्ट्रेन के कारण बाहर रहना अच्छा नहीं था। लेकिन हां, मैं मजबूत महसूस कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि हम जीत गए।

विराट बोले, मैं अभी भी पूरी तरह फिट नहीं

लखनऊ। रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के पूर्व कप्तान विराट कोहली का कहना है कि वह अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं आर उनके घुटने में सूजन बना हुआ है। विराट ने इसके बाद भी लखनऊ सुपर जाइंट्स के शानदार पारी खेली थी। इससे आरसीबी ने लखनऊ को 5 विकेट से हरा दिया था। मैच के बाद विराट से जब उनकी फिटने का लेकर पूछा गया तो उन्होंने माना है कि वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। कोहली ने कहा, मेरा घुटना हालांकि पिछले मैच की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। पिछले मैच के दौरान घुटने में काफी सूजन थी। इतना ही नहीं, पिछले 4-5 दिनों से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और मैं स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। इन शारीरिक परेशानियों के बाद भी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 49 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया। कोहली को हालांकि इस बात का दुख है कि वह मैच समाप्त नहीं कर पाये। इस मैच में लखनऊ द्वारा दिए गए 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, आरसीबी के लिए कठिन पिच पर रन बनाना आसान नहीं था। ऐसे में विराट ने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने पिच की स्थिति को देखते हुए पावरप्ले का पूरा लाभ फायदा उठाया। कोहली ने अपनी पारी में 6 चौके और 1 शानदार लगाकर लखनऊ के गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में ही पीछ कर दिया। उनहोंने देवदत्त पडिक्कल 10 रन के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रनों की अहमम साझेदारी कर टीम की अच्छी शुरुआत की।

सीएसके ने दोसा इडली गाने को लेकर बीसीसीआई से आरसीबी की शिकायत की

बेंगलुरु। इंडियन पीमियर लीग (आईपीएल) में एक नया विवाद शुरु हो गया है। सीएसके ने इस माह की शुरुआत में 5 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मैच में दोसा इडली गाने के जरिये राज्य का मजाक उड़ाने का आरोप रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) पर लगाया है। इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से इस मामले में शिकायत भी की है। अब देखना है कि बोर्ड इसपर क्या कदम उठाता है। अपनी शिकायत में सीएसके ने कहा कि है इस गाने से उनके प्रशंसकों की भावनाओं को ठेस लगी है। एक रिपोर्ट के अनुसार सीएसके ने कहा कि गाने में दोसा, इडली, सांभर, चटनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जबकि उनका मानना है कि यह उनके तमिलनाडु की पहचान का मजाक उड़ाने और उसे एक ही दायरे में सीमित करने का प्रयास था। सीएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने कहा कि आमतौर पर डीजे घरेलू टीम का समर्थन करने के लिए होते हैं पर इसके विपरीत चिन्नास्वामी स्टेडियम में हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ टिप्पणियां की गईं और इसी कारण हमने बीसीसीआई को इस मामले को एक पत्र भी लिखा है। गौरतलब है कि ये विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी।

बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को हराकर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बनाई जगह

म्यूनिख

जर्मनी के दिग्गज क्लब बायर्न म्यूनिख ने स्पेन के रिकार्ड 15 बार के चैंपियन रियल मैड्रिड को बुधवार रात एक रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हराकर (कुल स्कोर 6-4) यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मुकाबले में आखिरी पलों में लुइस डियाज और माइकल ओलिसे के गोल ने बायर्न को यादगार जीत दिलाई।मुकाबले के 89वें मिनट में लुइस डियाज ने गोल कर बायर्न को बढ़त दिलाई, जबकि इंजरी टाइम में माइकल ओलिसे ने गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ बायर्न अब सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन से भिड़ेगा। मैच के 86वें मिनट में रियल मैड्रिड के मिडफील्डर एडुआर्डो कामाविंगा को दो पीले कार्ड मिलने के बाद मैदान से बाहर कर दिया गया। इसके बाद मैच के अंत में आर्डा गुलर को भी असंतोष जताने पर रेड कार्ड मिला, जिससे टीम की वापसी की उम्मीदों को झटका लगा।

पहले हाफ में गोलों की बरसात

मुकाबले की शुरुआत बेहद तेज रही और सिर्फ 35 सेकंड में ही आर्डा गुलर ने गोल कर रियल को बढ़त दिलाई। इसमें बायर्न के गोलकीपर मैनुअल नायर की बड़ी गलती रही। हालांकि बायर्न ने पांच मिनट बाद ही अलेक्जेंडर पावलोविच के हेडर से बराबरी कर ली। 29वें मिनट में गुलर ने शानदार फ्री-किक से रियल को फिर बढ़त दिलाई, लेकिन हैरी केन ने आठ मिनट बाद गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया। इसके बाद किलियन एम्बाप्पे ने हाफ टाइम से ठीक पहले गोल कर मुकाबला बराबरी पर ला दिया।

दूसरे हाफ में दिखा संघर्ष और अंत में बायर्न की जीत

दूसरे हाफ में खेल की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन दोनों टीमों ने मौके बनाए। मैनुअल नायर ने शानदार बचाव कर बायर्न को मैच में बनाए रखा। हालांकि अंत में कामाविंगा के रेड कार्ड के बाद बायर्न ने इसका पूरा फायदा उठाया और लगातार दो गोल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। बायर्न के कोच विन्सेंट कोम्पनी ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा, यह क्लब के लिए शानदार रात रही।

पीएसएल को आईपीएल से बेहतर बताने के प्रयास में हंसी का पात्र बन रही पीसीबी

लाहौर। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी इन दिनों अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल), का आनंद उठा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में आईपीएल से पीएसएल की तुलना का जुनून छाया हुआ है और पाक क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पीएसएल को बेहतर बताने का प्रयास कर रहा है पर इससे वह हंसी का पात्र भी बना रहे हैं। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी अक्सर आईपीएल के ऊपर पीएसएल की श्रेष्ठता के दावे करते रहते हैं। उनका कोई भी बयान भारत या आईपीएल का जिक्र किए बिना शायद ही पूरा होता हो। हाल ही में, जब पाकिस्तान में तेल संकट के कारण पीएसएल के मैच खाली स्टेडियम में खेले जा रहे थे, और दर्शकों की अनुमति पर सवाल उठे, तब नकवी ने मीडिया से बातचीत में आईपीएल को लाने के प्रयास किये। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जहां पीएसएल के मुकाबले पेट्रोल-डीजल की कमी के कारण खाली स्टेडियम में हो रहे हैं, वहीं आईपीएल के मैच दर्शकों की खचाखच भीड़ के सामने खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार और मीडियाकर्मी भी पीएसएल में खेल रहे विदेशी क्रिकेटरों से बार-बार आईपीएल और पीएसएल की तुलना को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। उनकी तलाश इस बात की होती है कि कोई खिलाड़ी आईपीएल को लेकर कुछ नकारात्मक बोल दे, ताकि वे पीएसएल की श्रेष्ठता का ढोल पीट सकें। हाल ही में, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने श्रीलंकाई क्रिकेटर कुसाल मेंडिस से पूछा कि क्या उन्हें पिछले साल आईपीएल (गुजरात टाइटन्स) के लिए पीएसएल छोड़ने का कोई मलाल है, खासकर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, जबकि अब पीएसएल उन्हें दोबारा मौका दे रहा है और आईपीएल ने उन्हें नहीं चुना। मेंडिस ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।

मैच के दौरान रील बनाने में महिला की अंगूठी गुमी, 70 हजार का हुआ नुकसान

मोहली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक मैच के दौरान रील बनाने के दौरान एक महिला की 70 हजार रुपये की अंगूठी खो गयी। यहां के पीसीए स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के दौरान इस महिला ने वायरल रिंग ट्रेंड के लिए रील बनानी शुरु कर दी पर इसी दौरान उसकी 70,000 रुपए की महंगी अंगूठी खो दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में महिला एक लोकप्रिय रिंग ट्रेंड को दोहराने की कोशिश कर रही थी, इसमें लोग रिकार्डिंग करते समय अपनी अंगूठी को हवा में उछालने का नाटक करते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं पर यहां ये प्रयास उल्ट पड़ गया। अंगूठी को सुरक्षित रूप से पकड़ने के बजाय, उसने गलती से उसे नीचे गिरा दिया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंगूठी उसके हाथ से फिसलकर नीचे जा गिरी।

अंगूठी के हाथ से फिसलते ही महिला परेशान हो गयी। इस घटना के बाद वह तुरंत अपनी सीट और आसपास के क्षेत्र में अपनी खोई हुई अंगूठी को तलाशन में जुट गई। स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ और अव्यवस्थित माहौल में अपनी कीमती अंगूठी को ढूंढना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इसका एक वीडियो एक दर्शक ने साझा किया। इसमें अंगूठी के गुम होने का पूरा मामला दिखाया गया है।

गुम हुई अंगूठी की कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है। वीडियो के साथ लिखा गया है, 70,000 हजार का नुकसान हो गया। अंगूठी अभी भी नहीं मिली है। महिला ने स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शकों और सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी वह अंगूठी मिले, तो उसे वापस लौटाने में मदद करें। इसमें लिखा है, अगर स्टेडियम में मौजूद कोई भी व्यक्ति यह वीडियो देख रहा है, तो कृपया हमारी अंगूठी ढूंढने और उसे वापस लौटाने में हमारी मदद करें। यह घटना सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग महिला के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया में हो सकता है आईपीएल का अगला सत्र

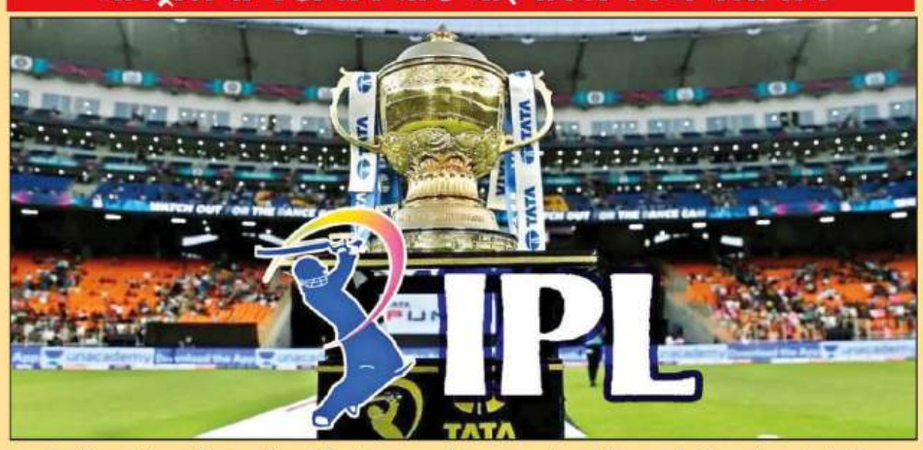

मुम्बई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) पिछले 18 साल में लगातार आगे बढ़ने के साथ ही दुनिया की सबसे लोकप्रिय टी20 लीग बन गई है। इसकी आपार लोकप्रियता और वैश्विक अपील को देखते हुए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी कई बार इसके मुकाबलों को विदेशी धरती पर भी आयोजित किया है, अरब अमीरात की धरती हो या दक्षिण अफ्रीका के मैदान पर जगह इसके मुकाबले सफल रहे हैं। अब अगले सत्र में आईपीएल के आस्ट्रेलिया में आयोजन की संभावनएं बन रही हैं। यह कदम लीग के वैश्विक होने की दिशा में एक और मजबूत कदम होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, आस्ट्रेलिया का एडिलेड ओवल स्टेडियम अगले साल मार्च में एक नियमित सत्र के आईपीएल मैच की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। एडिलेड ओवल के चेयरमैन जेमी ब्रिग्स और दक्षिण आस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन (एसएसीए) के प्रमुख विल रेयनर ने ये बात ही है। इस योजना पर कई हितधारकों के साथ प्रारंभिक चर्चाएँ हो चुकी हैं हालांकि बीसीसीआई से अभी तक औपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया गया है। यह देखना होगा कि बीसीसीआई इस अनूठे प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देता है। वहीं आईपीएल के बदले में आस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (बीबीएल) भी चेन्नई में एक मैच आयोजित करने पर विचार कर सकती है। इससे देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को मजबूत होने की संभावना है। एडिलेड को इस संभावित आयोजन के लिए कई कारणों से उपयुक्त माना जा रहा है।

यश डबास के विस्फोटक शतक से पीजीडीएवी कालेज ने दर्ज की 175 रन की बड़ी जीत

नई दिल्ली

तीसरे स्वामी दयानंद सरस्वती टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान पीजीडीएवी कालेज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को शिवाजी कालेज को 175 रनों के विशाल अंतर से पराजित कर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

इस मुकाबले के हीरो रहे यश डबास, जिन्होंने महज 51 गेंदों में 161 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 16 चौके और 15 छक्के जड़े। उनके अलावा श्रेष्ठ यादव (58) और अंकित कुमार (53) ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम के स्कोर को मजबूती दी।

पहले बल्लेबाजी करते हुए पीजीडीएवी कालेज ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 332 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में शिवाजी कालेज की टीम 15.3 ओवर में 157 रन पर सिमट गई। शिवाजी कालेज की ओर से प्रियांश सिंह ने सर्वाधिक 37 रन बनाए, जबकि धैर्य मल्होत्रा ने गेंदबाजी में तीन विकेट हासिल किए।

पीजीडीएवी कालेज की ओर से वैभव पांडे (13 रन देकर 4 विकेट) और प्रणीत (17 रन देकर 3 विकेट) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम को संभलने का मौका नहीं दिया। यश डबास को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन आफ द मैच चुना गया, यह पुरस्कार डा. पवन डबास ने प्रदान किया।

करण सोनी का आलराउंड प्रदर्शन, पीजीडीएवी येलो टीम की जीत

टूर्नामेंट के एक अन्य मुकाबले में पीजीडीएवी येलो टीम ने शहीद भगत सिंह कालेज को 87 रनों से हराया। इस मैच में करण सोनी ने शानदार आलराउंड प्रदर्शन करते हुए 52 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 12 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए 11 रन देकर 3 विकेट झटके।

नैतिक यादव (40) और अंश जाखड़ (3/38) ने भी टीम की जीत में अहम योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीजीडीएवी येलो टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 265 रन बनाए। जवाब में शहीद भगत सिंह कालेज की टीम 19.2 ओवर में 178 रन पर आलआउट हो गई।

पराजित टीम की ओर से वरदान सूरी ने 23 रन बनाए, जबकि अभय और शास्वत ने दो-दो विकेट हासिल किए।

गुजरात के खिलाफ मैच में ग्रीन को बाहर करेगी सीएसके

मुम्बई

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस 19 वें सत्र में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का प्रदर्शन बेहद खराब है और वह पांच मैचों में एक भी जीत नहीं पायी है। उसका एक मैच बारिश से रद्द हो गया था जिससे उसका केवल एक अंक है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले के अलावा उसकी टीम एक भी मैच में संघर्ष नहीं कर पायी। केकेआर की इस खराब हालत के लिए आलराउंडर कैमरुन ग्रीन सहित सभी टीम के कुछ खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन है। ऐसे में अब देखना है कि शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले मैच में ग्रीन को शामिल किया जाता है या नहीं। सबसे महंगे खरीदे गये ग्रीन इस सत्र में एक भी मैच में रन नहीं बना पाये हैं और गेंदबाजी में भी विफल रहे हैं। ऐसे में उनकी जगह किसी अन्य को उतारने की मांग की जा रही है। इसके अलावा टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण भी कमजोर है, दो मुख्य स्पिनर

में से एक आउट आफ फार्म है और बल्लेबाजी में भी दम नहीं है।

चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ मंगलवार रात हुई हार ने उनकी कमी को दिखाया है। 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम असफल रही। पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने तो यहां तक कह दिया कि टीम की बल्लेबाजी में तकनीकी खामी है। सुनील नारायण को को पारी की शुरुआत के लिए भेजने का फैसला एक नया प्रयोग था जो असफल रहा। वह 17 गेंदों में 24 रन ही बना पाये।

फिंच ने अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी की 31 गेंदों में 50 रन की साझेदारी पर भी निराशा व्यक्त की। उनके अनुसार, इस साझेदारी में आक्रमक अंदाज नहीं था। यह विरोधी टीम के कप्तान को अपनी रणनीति में बदलाव के बारे में मजबूर नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, कुछ दूसरे फैसले थोड़े अजीब थे जिससे लगा कि टीम जीत की दौड़ में शामिल नहीं थी।

टीम के बालिंग कोच टिम साउदी ने हालांकि इन फैसलों को अलग-अलग विकल्प आज़माने और टीम की गहराई को परखने का प्रयासद बताया। उन्होंने कहा कि हारने पर ऐसे विकल्प तलाशना स्वाभाविक है और यह आईपीएल की खूबसूरती है। मंगलवार को, केकेआर ने नारायण और फिन एलन के साथ ओपनिंग की। एलन ने सिर्फ 1 रन बनाया, और उनके इस इस में केवल 37, 28, 6, 9 और 1 रन ही बनाये हैं।

युवा तेज़ गेंदबाज़ कार्तिक त्यागी ने की अच्छी वापसी

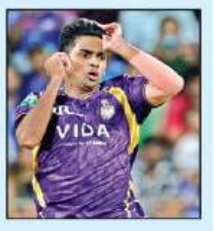

कोलकाता। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के युवा तेज़ गेंदबाज़ कार्तिक त्यागी ने लंबे समय के बाद खेल के मैदान पर जबरदस्त वापसी की है। कार्तिक ने फिटनेस हासिल करने के लिए साल 2024 में खेल से ब्रेक ले लिया था। अब जबकि व 19 महीने के बाद मैदान पर लौटे हैं जो उनमें एक अलग से आत्मविश्वास दिख रहा है। वह केवल अपनी पुरानी गति वापस पा चुके हैं, बल्कि एक नए एक्शन के साथ ही परिपक्व होकर आये हैं। पिछले कई साल त्यागी के लिए परेशानी भरे रहे, जब 2021 से लगातार परेशान कर रही पिंडली की चोट से वह मैदान से दूर रहे। कई सुविधाओं पर नियमित पुनर्वास के बावजूद, चोट पहले की तस बनी हुई थी, और वे 2022 से 2024 के आईपीएल सीजन के बीच केवल छह आईपीएल मैच ही खेल पाए। दिसंबर 2023 से मई 2024 के बीच, वे केवल 10 शीर्ष-स्तरीय मैचों में खेल पाए। इस गेदबाज ने कहा, मैं बड़े मैच नहीं खेल पा रहा था। मैं अभ्यास में भी ज्यादा ओवर नहीं फेंक पा रहा था। 2024 आईपीएल से पहले, उन्होंने अपनी पिंडली की चोट का इलाज करने का संकल्प लिया था, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें एक साइड स्ट्रेन भी हो गया। उन्होंने स्वीकार किया, यह बहुत मुश्किल था, और तभी मुझे समझ आया कि मुझे पहले इसका ठीक से इलाज करना चाहिए इसी सोच के साथ त्यागी ने क्रिकेट से 19 महीने का ब्रेक लिया, जो उनके लिए बेहद जरूरी था। इस दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के पूर्व मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट आशीष कौशिक से सलाह ली।

गर्मी आ गई है और दुनिया के कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो गई है। पानी की कमी के कारण लोगों की जानें भी जा रही हैं। पिछले दिनों नन्ही बच्ची पानी भरते-भरते मर गई। डॉक्टरों ने बच्ची की मौत का कारण डीप हीट स्ट्रोक को माना है। 11 साल की बच्ची रोजाना तपती धूप में पानी भरती थी। उसका घर हैंडपंप से 400 मीटर दूर था। वो रोज 10 से ज्यादा बार पानी भरने जाती थी। उस दिन गर्मी ज्यादा थी या धूप, मालुम नहीं। लेकिन बच्ची हीट स्ट्रोक की शिकार हुई और पानी की आस में परिवारजनों से हमेशा के लिए दूर हो गई है।

पानी की किल्लत होने पर इस तरह पूरी करें पानी की जरूरत

हीट स्ट्रोक

साल दर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी ने इस साल अप्रैल में ही तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर लिया। ऐसे में बढ़ते तापमान और आ रही लोगों की मौत की खबरों के बीच जरूरी है कि आप भी हीट स्ट्रोक के खतरों को आब सामान्य तौर पर लेने के बजाय इसके खतरे को समझें और बचकर रहें।

इन इलाकों में समस्या

जल समस्या देश के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अलावा मध्यप्रदेश के भी जिलें सुखे की चपेट में है। दक्षिणी कर्नाटक के ग्रामीण इलाक पूरी तरह से सूख चुके हैं और वहां से दंगों की खबरें आ रही हैं। बारह महीने सदाबहार रहने वाले चेरापूंजी में भी पानी की समस्या सुनने को आ रही है। दिल्ली में पानी की समस्या तो गर्मी के शुरू होते ही शुरू हो जाती है। बिहार जैसे राज्य में जहां हर वर्ष बाढ़ आती है वो भी पानी की समस्याओं से जूझ रहा है।

जल समस्या

जल इंसानी जीवन का जरूरी अंग है। एक सामान्य इंसान को प्रतिदिन आठ ग्लास पानी पीने की जरूरत होती है। डेली इनटेक के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को प्रति दिन 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए और महिलाओं को 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए। इसमें खाने और फलों में मौजूद पानी को भी शामिल किया गया है। लेकिन जब इतनी मात्रा में पानी नहीं मिल पाता तो शुरू होती है जल समस्या।

समस्या से निपटने के लिए ये करें

पानी का कम से कम इस्तेमाल करना जल-समस्या के निवारण का पहला कदम है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है

कि पानी का कम इस्तेमाल कितना करें। क्योंकि लोगों के पास जब तीन दिन में पानी आएगा तो वे कम इस्तेमाल करेंगे ही। तो फिर कम इस्तेमाल कैसे?

- कम इस्तेमाल करने की बात उन लोगों के लिए है जिनके पास पानी की उचित व्यवस्था है।
- नदियों, तलाबों, हैंडपंप औदि जल स्रोतों को कम से कम प्रदूषित करें।
- दवाईयों का छिड़काव- रोग-जनक सूक्ष्म जीव पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं। जिससे वो इंसान के पीने लायक नहीं होता। इस पानी को पीने से पेट की बीमारियां होती हैं। इससे बचने के लिए जलस्रोतों में दवाईयों का छिड़काव करें।
- जल की जांच करें- कई बार स्वच्छ जल भी बीमार कर देते हैं। दरअसल जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ और गैसें घुली होती हैं जो कई बार अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं। जिससे पानी पीने लायक नहीं रहता।
- गंदगी का निपटान करें- घरों से निकले कचरे जैसे- नहाने, धोने, पोछा लगाने, सड़े फल, तरकारियों, साबुन और डिटर्जेंट आदि के कारण पानी प्रदुषित होता है।
- पानी बचाएं- पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। साथ ही वर्षा के जल का संचयन

करें।

किल्लत में ये करें

- कम पानी पिएं।
- तला-भूना कम खाएं।
- अधिक से अधिक फल खाएं।
- नहाने के लिए ज्यादा पानी बर्बाद ना करें।
- कपड़ें धोने के पानी से ही घर को पोछें।
- अलग से घर धोने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें।

जब सहा न जाए दर्द

स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए हम तमाम जतन करते हैं, लेकिन आज की जीवनशैली में कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें दबे पांव हमारे पास आ ही जाती हैं। ऐसी ही तकलीफों में शामिल है दर्द। कुछ दर्द तो ऐसे होते हैं, जो हमें छोड़ते ही नहीं। इन्हें डॉक्टरी भाषा में क्रॉनिक पेन कहा जाता है।

तमाम जतन के बाद भी कुछ दर्द ठहर जाते है। महीनों चले इलाज में हमें यह भ्रम जरूर होता है कि अब यह दर्द लौट कर नही आएगा, लेकिन तब तक दर्द अपनी नींव और मजबूत कर चुका होता है। दुनियाभर की दवाएं, इंजेक्शन, शारीरिक थैरेपी आदि कराने का कोई फायदा नहीं होता।

डॉक्टरी भाषा में ऐसे दर्द को 'क्रॉनिक पेन' यानी स्थाई दर्द कहते हैं, जो समय के साथ जाता नहीं, रुक जाता है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक चार भारतीय महिलाओं में से एक और हर दस में एक पुरुष को कमर दर्द की समस्या है। हमारे देश में यह समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन साथ निभाने वाली इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा, कोई तो उपाय ऐसे होंगे, जिनकी सहायता से जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को हमेशा के लिए अलविदा कहना आसान होगा। आज उन्हीं रास्तों के बारे में बात करते हैं।

दिमाग और दर्द

कई महीनों तक एक ही स्थान पर हो रहे दर्द के हम धीरे-धीरे आदी हो जाते हैं। इलाज होने के बाद भी हम उस जगह के दर्द को लेकर सचेत रहते हैं और हमें दर्द महसूस होने लगता है। मनोचिकित्सकों की मानें तो कभी-कभी वास्तव में दर्द न होते हुए भी हम किसी खास जगह पर दर्द महसूस करने लगते हैं। जिस तरह थकान न होने पर भी यदि हम ऐसा महसूस करें तो थकान महसूस होने लगती है।

जब सताए जोड़ों का दर्द

हम में से हर चौथा व्यक्ति जोड़ों के दर्द से परेशान है। तेज भागती जिन्दगी की रफ्तार के बीच दबे पांव यह कब आ जाता है, पता नहीं चलता। हड्डियों के विशेषज्ञ के मुताबिक जोड़ों के दर्द की शुरुआत में ही हमें सचेत हो जाना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार शुरुआती दौर में ही यदि हम नियमित व्यायाम करें और उपचार कराएं तो दर्द से राहत मिल जाती है। लेकिन दर्द पुराना हो जाए तो उसे उपचार और व्यायाम से ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए महंगी सजर्री करानी पड़ सकती है। हालांकि सजर्री सबसे आखिरी स्थिति है।

ऐसे रखें जोड़ों का खयाल

काम करने का तरीका बदलें: हम में से अधिकांश लोग कंप्यूटर के सामने घंटों काम करते हैं, लेकिन अपने बैठने के तरीकों पर ध्यान नहीं देते। कुर्सी पर बैठते हुए हमारी पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपकी कुर्सी बहुत नीचे ना हो। इसके अलावा अगर आप काफी देर तक टाइप करते हैं तो अपनी अंगुलियों को थोड़ा आराम दें, क्योंकि काफी देर तक टाइपिंग की वजह से आपकी अंगुलियों में दर्द का ठहराव हो सकता है। अगर संभव हो तो अपने घुटनों को कमर से ऊपर रखें। इसके लिए आप पैरों के नीचे कुछ रख सकते हैं।

थोड़ा आराम भी है जरूरी: जोड़ों में दर्द खासकर कमर का दर्द लगातार काम करने की वजह से बढ़ जाता है, इसलिए शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। हमारी हड्डियों की क्षमता की एक सीमा है। उससे ज्यादा समय तक काम करने पर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इनका आराम करना भी उतना ही जरूरी है।

गुनगुने पानी में डुबो कर रखें: मांसपेशियों और हड्डियों को राहत देने में गुनगुना पानी कारगर साबित होता है। दिनभर के काम के बाद कुछ देर शरीर को गुनगुने पानी में डुबो कर रखें। इससे मांसपेशियों और हड्डियों में नई ऊर्जा का संचार होगा और दर्द से आराम मिलेगा।

योग और व्यायाम करें

हड्डियों को सपोर्ट देने वाली मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके लिए योग और व्यायाम की सहायता ली जा सकती है। योग और व्यायाम काफी हद तक हमें कई बीमारियों से दूर रखते हैं। इसके अलावा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं।

डॉक्टरी सलाह

- घुटनों में या दूसरे जोड़ों में बहुत दर्द हो तो उन पर ज्यादा जोर ना डालें, इससे स्थिति और खराब हो सकती है।
- किसी भी चमत्कारी दवा का इस्तेमाल ना करें। कई बार चमत्कारी दवा के नाम पर लोग धोखा करते हैं।
- खाने-पीने का खास ध्यान रखें और खाने में दूध और अंडे को शामिल करें।
- सिर्फ उसी व्यायाम या योग को आजमाएं, जिसमें जोड़ों पर बहुत ज्यादा जोर ना पड़ता हो।

हेल्दी खाएं

हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम सबसे उपयोगी माना जाता है। ठंडी जगहों में रहने वालों को तो सप्लिमेंट के तौर पर विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक हमारी हड्डियों के आसपास एक खास किस्म का तरल पदार्थ होता है, जिसकी वजह से वे घूमती और मुड़ती हैं। जैसे-जैसे यह तरल पदार्थ कम होता है, हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ता है। इस तरह से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और धीरे-धीरे घिसने लगती हैं। इसलिए इनका संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर ओमेगा-3 फैटी एसिड लेने की सलाह देते हैं। मछली में यह भरपूर मात्र में पाया जाता है। विटामिन डी के लिए धूप और कैल्शियम के लिए दूध सबसे अच्छा स्रोत है।

ऐसे चलता है दर्द का चक्र

- दर्द शुरू होता है।
- आपकी सक्रियता कम हो जाती है।
- डॉक्टर के पास जाते हैं।
- टैस्ट कराते हैं और कई सारी दवाएं लेते हैं।
- दर्द में राहत मिलता है।
- आप ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं।
- पहले से ज्यादा दर्द महसूस करते हैं।
- सक्रियता और कम हो जाती है।
- बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है।
- ताकत में कमी पाते हैं।

सहयोग ही है सबसे बड़ा इलाज

शुरुआती दौर में डिमेंशिया की स्थिति में परिवार रोगी की मनोदशा व स्थिति को उम्र का असर मान अनदेखा करता है। यह उपेक्षा सहन न करने के कारण रोगी विरोध का सा माहौल बना लेता है और इमोशनल ट्रॉमा की अवस्था बन जाती है। हालांकि ऐसे में न्यूरोलॉजिस्ट काउंसलिंग कराने की सलाह देते हैं। सबसे बड़ा और कारगर इलाज है घर वालों का सहयोग। जो रोगी है, वह अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन घर वाले जानें कि यह बीमारी है और उन्हें इसमें पूरा सहयोग कर न केवल रोगी की स्थिति सुधारने में मदद करें, बल्कि यहां-वहां घूम कर व्यर्थ पैसा व श्रम बेकार न करें। जितनी जल्दी यह रोग पहचाना जाए, उतना ही अच्छा है। समय पर इलाज कराने से रोगी की स्थिति नियंत्रण में रहेगी। इलाज के दौरान लगने वाला समय अत्यंत लंबा हो सकता है, इसलिए परेशान न हों। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी परिवारजनों की है, क्योंकि वे ही सबसे पहले स्वभाव में आए परिवर्तनों को देख पाते हैं। रोगी की सही देखरेख और आत्मीयता उसके लिए मददगार हो सकती है।

दिमागी कसरत है फायदेमंद

अल्जाइमर जैसे रोग को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का योगदान महत्वपूर्ण है। डॉक्टर इस बीमारी का इलाज भले ही न ढूंढ पाए हों, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमागी कसरत इस बीमारी को दूर रख सकती है। नई भाषा सीखें, गेम, डांस, संगीत और खेलों में समय लगाएं।

डाइट जो अल्जाइमर पर रखे नियंत्रण

ब्रेकफास्ट महत्वपूर्ण है शोध बताते हैं कि सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी के लिए जरूरी है। हेल्दी नाश्ते से दिमाग को ईंधन मिलता है। इससे याददाश्त इंप्रूव होती है व एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन ज्यादा कैलोरी वाला खाना आपको आलसी बनाता है और एकाग्रता में कमी लाता है।

चीनी कम

चीनी दिमाग को ईंधन देने का काम करती है, लेकिन टेबल शुगर नहीं, बल्कि खाने से मिला ग्लूकोज। तभी अत्यंत लो फील होने पर एक गिलास मीठा पेय आपको फुर्तीला बना देता है। एनर्जी बूस्टर का काम करता है कार्बोहाइड्रेट और शुगर। मधुमेह के शिकार हैं तो डाइटीशियन की सलाह लें।

मछली

प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है मछली। ओमेगा थ्री जैसा फायदेमंद ब्रेन टॉनिक और किसी में नहीं मिलता। यह ब्रेन फंक्शन के साथ स्ट्रोक के खतरे को भी

कम करती है। याददाश्त बढ़ाती है। हेल्दी ब्रेन व हार्ट के लिए सप्ताह में दो बार मछली खाएं।

नट्स

एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ विटमिन ई भी इनमें मौजूद है। नट्स हमार शरीर में बी टाइप की कोशिकाओं का सृजन करते हैं, जो एंटीबॉडीज बना कर हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती हैं। नट्स तनाव को झेलने की शक्ति भी देते हैं।

ब्लू बेरीज है सुपर ब्रेन फूड

रिसर्च बताती हैं कि बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स मस्तिष्क के लिए फायदेमंद हैं। यह फल फ्रीरेडिकल्स से होने वाले नुकसान से दिमाग को बचाता है, अल्जाइमर के खतरे को कम करता है। सीखने की क्षमता को बढ़ाता है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**